सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 148, नई दिल्ली । गुरुवार, 08 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

इंसान की नीयत अगर साफ नहीं तो कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे छोटा ही रहेगा।

03 दिल्ली में फरवरी से पहले होंगे चुनाव? क्यों लगाई जा रहीं अटकलें

06 ओलंपियाड की तैयारी जेईई में सफलता पाने में कैसे मदद कर सकती है

08 भाजपा मनाएगी 'हर घर तिरंगा', 'तिरंगा यात्रा' और विभाजन स्मृति

फ्री में मिलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनो के अलावा एक भी वाहन सरकारी राजस्व से खरीद कर परिवहन विभाग/ दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को नही दे पाया, फिर किस लिए प्रचार?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली की जनता को गुमराह करने वाला परिवहन विभाग क्या दिल्ली की जनता को सबूत पेश कर सकता है की

1. आम आदमी पार्टी सरकार के रहते सरकारी राजस्व का प्रयोग कर दिल्ली की जनता को क्या एक भी वाहन सार्वजनिक सवारी सेवा के लिए प्रदान किया है ?

2. दिल्ली परिवहन निगम के नाम का लोगो प्रयोग कर चलने वाला एक भी वाहन क्या दिल्ली परिवहन निगम के नाम पंजीकृत हैं?

3. दिल्ली परिवहन निगम का लोगो लगाकर दिल्ली की सड़को पर चलने वाले वाहनों के चालक क्या दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी है ?

4. दिल्ली में अब तक सार्वजनिक सवारी सेवा में आए इलैक्ट्रिक वाहनों में से क्या एक भी वाहन दिल्ली परिवहन निगम के नाम पर है ?

5. दिल्ली में सार्वजनिक सवारी सेवा में चलने वाले सभी वाहन प्राईवेट कंपनियों के नाम फिर दिल्ली में चल रही आरटीवी मिनी बसों को गैर कानूनी तरीके से समाप्त करने की साजिश क्यों ?

6. दिल्ली में ई रिक्शा पर उच्च न्यायालय के आदेश और उपराज्यपाल द्वारा जारी गैजेट नोटिफिकेशन के बाद भी आदेशित सड़को पर रोक ना लगाने का कारण?

7. निजी व्यक्ति के द्वारा परिवहन क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने की जगह रोक की तरफ ध्यान क्यों ?

मुख्य सचिव और उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा दिल्ली की जनता को गुमराह करने और परेशान करने के लिए विशेष परिवहन आयुक्त को मिली छूट के रहते परिवहन विभाग से जवाब की उम्मीद कम।

दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहन, दो लाख से ज्यादा हुई इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राजधानी में दो लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने चार साल पहले इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की थी। इस नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार शहर में चार्जिंग ढांचा तैयार कर रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दो लाख के पार पहुंच गई है। यह आंकड़ा साबित कर रहा है कि दिल्ली में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं जो इस बात का संकेत है कि पर्यावरण को लेकर भी दिल्ली के लोग जागरुक हो रहे हैं। पिछले चार साल में दिल्ली में दो लाख 15 हजार इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। इसमें सबसे अधिक दो पहिया हैं, जिनकी संख्या एक लाख के करीब है। 2 हजार इलेक्ट्रिक बसें है तो 17 हजार तिपहिया हैं और 57 हजार ई-रिक्शा शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक वाहन 2023 में पंजीकृत हुए हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। इसी दिशा में सरकार काम कर रही है।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के चार साल

यहां गौरतलब है कि आठ अगस्त को दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को चार साल पूरे हो रहे हैं। इस नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। सरकार वर्तमान नीति को जल्द ही विस्तार देने जा रही है और नई बनाई जा रही इस नीति में भी कई तरह की रियायतें देने की सरकार की योजना है।

सरकार चार्जिंग ढांचा तैयार कर रही

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार शहर में इस तरह का चार्जिंग ढांचा तैयार कर रही है कि लोगों को हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन मिले या बैट्री बदलने यानी बैट्री स्वैपिंग की भी सुविधा मिल सके। दिल्ली सरकार का मानना है कि 2025 तक कुल वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तभी हो पाएगी, जब दिल्ली में वाहन चार्जिंग के लिए बेहतर ढांचागत सुविधा होगी।

दिल्ली मेट्रो-बस अड्डों के पास चार्जिंग स्टेशन

इसके लिए आधारभूत ढांचा को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए पिछले साल अतिरिक्त 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बैट्री स्वैपिंग की भी सुविधा भी शुरू की गई है। इनमें से अधिकांश दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के मेट्रो स्टेशनों और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) डिपो पर लगाए गए हैं। राजधानी में अलग-अलग एजेंसियों व योजनाओं के अंतर्गत पांच हजार से अधिक चार्जिंग प्वाइंट बन गए हैं। इनमें 318 बैट्री स्वैपिंग स्टेशन भी हैं।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैरियर लगाकर बनाई अवैध पार्किंग वाहनों से रकम वसूलता रहा ठेकेदार; अधिकारी बेसुध

पार्किंग ठेकेदार ने शुक्रवार से अजमेरी गेट की तरफ बैरियर लगाकर स्टेशन परिसर में आने वाले प्रत्येक वाहन से 40 रुपये शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। रेलवे के अधिकारी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जब इसके वीडियो अधिकारियों को भेजने शुरू किए तो रेलवे ने कार्रवाई की। पहले तो रेलवे ने कोई कार्रवाई नहीं की बाद में उस पर जुर्माना लगाया।

नई दिल्ली। दिल्ली रेल प्रबंधक कार्यालय के बगल में स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार अवैध रूप से बैरियर लगाकर वाहन चालकों से कई दिनों तक वसूली करता रहा। मामला सामने आने के बाद ठेकेदार पर 50 हजार रुपये जुर्माना करने के साथ ही उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ पहले एक्सेस कंट्रोल पार्किंग व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में कुछ मिनट तक वाहन रोकने पर भी पार्किंग शुल्क देना पड़ता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

40 रुपये लेना शुरू किया

अब सिर्फ पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर ही शुल्क लिया जा सकता है। टेंडर के इस नियम का उल्लंघन कर पार्किंग ठेकेदार ने शुक्रवार से अजमेरी गेट की तरफ बैरियर लगाकर स्टेशन परिसर में आने वाले प्रत्येक वाहन से 40 रुपये शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया।

अधिकारी लीपापोती कर रहे

इससे संबंधित वीडियो भी रेलवे अधिकारियों को भेजा। शुरू में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मामला तूल पकड़ने पर बैरियर हटाने के साथ ही ठेकेदार पर जुर्माना लगाकर मामले की लीपापोती शुरू कर दी गई है। दिल्ली मंडल के अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि जानकारी मिलते ही दो दिन बाद बैरियर हटा दिया गया था।

मामल की होनी चाहिए जांच

इस संबंध में रेलवे अधिकारी उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने मंडल सह मंत्री इंद्रजीत सिंह ने कहा, इस मामले की जांच होनी चाहिए। बिना अधिकारियों की मिलीभगत से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह संभव नहीं है। सीसीटीवी फुटेज से यह पता किया जाना चाहिए कि कितने वाहनों से अवैध उगाही की गई है। ठेकेदार से पूरी रकम वसूलने के साथ ही उसका ठेका समाप्त किया जाना चाहिए।

सड़क हादसों में आएगी कमी... दिल्ली बस ड्राइवरों पर लागू होंगे नए नियम, परिवहन मंत्री ने की घोषणा

दिल्ली की सड़कों पर बढ़ रहे बस हादसों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस ड्राइवरों के लिए नई नियमावली लागू करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ नए एहतियाती कदम उठाने की घोषणा की।

नई दिल्ली : बसों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और राहगीरों के साथ-साथ बस यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार कुछ नए और सख्त कदम उठाने जा रही है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस ड्राइवरों के लिए नई नियमावली लागू करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ नए एहतियाती कदम उठाने की घोषणा की। पिछले दिनों कुछ बस हादसे हुए थे, जिन पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने यह पहल की। 29 जुलाई को परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन उपायों को मंजूरी दी गई थी। ये नए नियम डीटीसी और क्लस्टर स्कीम की बसें चला रहे सभी ड्राइवरों (कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट) पर लागू होंगे।

आधार बेस्ड ड्यूटी एलोकेशन

डीटीसी और डिम्ट्स के जितने भी ड्राइवर हैं, उन सबकी आधार बेस्ड ड्यूटी लगाई गई। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डिवेलप किया जा रहा है, जिसकी मदद से आधार बेस्ड ड्यूटी एलोकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि कोई भी ड्राइवर डबल शिफ्ट न कर सके। इसके लिए सभी ड्राइवरों का एक यूनिफाइड डेटाबेस भी बनाया जा रहा है, जिसका एक्सेस सभी डिपो मैनेजरों के पास होगा। अगर किसी ड्राइवर ने एक शिफ्ट कर ली है, तो वह अपने आप दूसरी शिफ्ट के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा और उसकी डबल ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी।

चेहरे से होगी ड्राइवरों की पहचान

प्रत्येक डिपो में बायोमैट्रिक फेस रिकग्निशन सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। इसके लिए टेंडर नोटिस जारी किया जा चुका है। जब भी कोई ड्राइवर ड्यूटी के लिए आएगा, तो यह सिस्टम ड्राइवर के चेहरे से उसकी पहचान करके यह सुनिश्चित करेगा कि वह डबल ड्यूटी न कर सके। अगर इसके बाद भी किसी ड्राइवर के डबल ड्यूटी करने की शिकायत मिलती है, तो इसके लिए डिपो मैनेजर को जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

सिम्युलेटर पर होगी ट्रेनिंग

डीटीसी और क्लस्टर बसों के कई ड्राइवर दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं और उनके पास अन्य राज्यों से जारी हैवी व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है। अभी ऐसे ड्राइवरों को इंडक्ट करने से पहले उन्हें डीटीसी के नंद नगरी स्थित ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अब दिल्ली सरकार की बसें चलाने के लिए जरूरी स्किल्स पर आधारित ड्राइविंग सिम्युलेटर खरीदे जा रहे हैं। आगे चलकर इन्हीं सिम्युटेर्स पर ड्राइवरों का टेस्ट होगा। अगर कहीं से भी ऐसा लगता है कि ड्राइवर सेफ्टी के साथ ड्राइविंग नहीं कर पाएगा, तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा।

ब्लैक लिस्ट ड्राइवर नहीं दे सकेंगे गच्चा

अभी अगर कोई ड्राइवर एक डिपो या क्लस्टर से निकाल दिया जाता है, तो वह दूसरे डिपो या क्लस्टर में जाकर नौकरी कर लेता है। इसे रोकने के लिए सभी बस ड्राइवरों का एक कॉमन पूल बनाया जा रहा है। अगर किसी ड्राइवर ने कहीं पर भी कोई वॉयलेशन किया है या उससे कोई एक्सिडेंट हुआ है और इस वजह से उसे किसी डिपो या क्लस्टर से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, तो यूनिफाइड डेटाबेस की मदद से अब उसके बारे में तुरंत जानकारी मिल जाएगी और वह बस ड्राइवर के रूप में किसी भी दूसरी जगह पर नौकरी नहीं कर पाएगा।

ब्रीद एनालाइजर से जांच जरूरी

बस ड्राइवरों को ड्रंकन ड्राइविंग से रोकने के लिए सभी डिपो में ब्रीद एनलाइजर लगाए जाएंगे। डिपो मैनेजर को ड्यूटी देने से पहले प्रत्येक ड्राइवर का ब्रीदिंग टेस्ट करना होगा। ड्राइवर के लिए यह टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। अगर कोई ड्राइवर शराब पीकर ड्यूटी पर आता है, तो इस जांच से पता लग जाएगा कि वह नशे की हालत में है और उसे ड्यूटी करने से रोका जा सकेगा।

"लॉजिस्टिक्स उद्योग - ऊर्जा और संसाधनों का कुशल उपयोग"

डॉ. लॉजिस्टिक्स

आज के तेजी से बदलते हुए विश्व में, स्थिरता और पर्यावरण की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बन गए हैं। लॉजिस्टिक्स उद्योग, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस परिवर्तन के केंद्र में है। स्थिरता को अपनाने से न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है, बल्कि आर्थिक लाभ और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स उद्योग में स्थिरता का अर्थ है ऊर्जा और संसाधनों का कुशल उपयोग, अपशिष्ट को कम करना, और प्रदूषण को न्यूनतम करना। यह न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे उद्योग की लागत भी कम हो सकती है और संचालन की दक्षता बढ़ सकती है। लॉजिस्टिक्स उद्योग में ऊर्जा की बचत के लिए वाहनों में ईंधन की खपत को कम करने के लिए नए तकनीकी उपायों का उपयोग करना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाना और गोदामों तथा कार्यालयों में ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

अपशिष्ट प्रबंधन में पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की प्रक्रियाओं को लागू करना, अनावश्यक पैकेजिंग को कम करना और बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना शामिल है। इसके अलावा, अपशिष्ट को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना भी आवश्यक है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों का सख्ती से पालन करना, स्थायी परिवहन उपायों जैसे रेल और जल परिवहन का अधिक उपयोग करना, और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का उपयोग करना चाहिए ताकि ट्रैफिक और प्रदूषण को कम किया जा सके।

प्रौद्योगिकी का उपयोग भी स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल तकनीक और ऑटोमेशन का उपयोग लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ा सकता है। सस्टेनेबल सॉफ़्टवेयर और उपकरणों का उपयोग जो पर्यावरण की दृष्टि से अधिक लाभकारी हों, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग अपशिष्ट और ऊर्जा की खपत को कम करने में मदद कर सकते हैं।

श्रमिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों को स्थिरता की अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करना और उनके प्रशिक्षण में निवेश करना आवश्यक है। स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है।

लॉजिस्टिक्स उद्योग में स्थिरता को अपनाने की आवश्यकता आज के समय की मांग है। यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे उद्योग की कार्यक्षमता और लाभप्रदता भी बढ़ती है। स्थिरता को अपनाने से लॉजिस्टिक्स कंपनियां न केवल अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकती हैं, बल्कि वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकती हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम सभी मिलकर इस दिशा में सार्थक कदम उठाएं और स्थिरता को लॉजिस्टिक्स उद्योग का अभिन्न हिस्सा बनाएं।

डॉ. लॉजिस्टिक्स एक पहल है जो पाठकों को लॉजिस्टिक्स उद्योग की गहरी समझ प्रदान करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य है उद्योग के विभिन्न पहलुओं, कार्यों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालना, ताकि लोग इस क्षेत्र में बेहतर संभावनाओं और अवसरों को समझ सकें। यह पाठकों को लॉजिस्टिक्स के महत्व और इसकी जटिलताओं से अवगत कराकर उद्योग में उनकी समझ और दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है।

डॉ. अंकुर शरण (डॉ. लॉजिस्टिक्स)
drlogistics.ankur@gmail.com

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

उत्तर भारत में हरियाली तीज पर्व की विशेष छटा देखने को मिलती है

कुछ जगह इस पर्व को हरियाली तीज के नाम से भी पुकारा जाता है। इस पर्व के आने से पहले ही घर-घर में झूले पड़ जाते हैं। नारियों के समूह गीत गाते हुए झूला झूलते दिखाई देते हैं। इस दिन बेटियों को बढ़िया पकवान, गुजिया, घेवर, फैनी आदि सिंधारा के रूप में भेजा जाता है।

नई दिल्ली। महिलाएं चाहे किसी भी उम्र की हों सभी को श्रावणी तीज का इंतजार बेसब्री से रहता है क्योंकि इस पर्व के दौरान उनका जीवन एक बार फिर उमंगों से भर जाता है। इस पर्व पर नारियों के समूहों को झूलों पर झूलते, तरह-तरह के पकवान बनाते, खिलाते या सामूहिक गीत गाते देखा जा सकता है। उत्तर भारत में इस पर्व की विशेष छटा देखने को मिलती है। राजस्थान और पंजाब में तो यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से पारम्परिक अंदाज में मनाया जाता है वहीं दिल्ली तथा एनसीआर में बाजार इस त्योहार पर काफी हद तक हावी हो चुका है।

कुछ जगह इस पर्व को हरियाली तीज के नाम से भी पुकारा जाता है। इस पर्व के आने से पहले ही घर-घर में झूले पड़ जाते हैं। नारियों के समूह गीत गाते हुए झूला झूलते दिखाई देते हैं। इस दिन बेटियों को बढ़िया पकवान, गुजिया, घेवर, फैनी आदि सिंधारा के रूप में भेजा जाता है। इस दिन सुहागिनें बायना छूकर सास को देती हैं। इस तीज पर मेंहदी लगाने का विशेष महत्व है। स्त्रियां हाथों पर मेंहदी से भिन्न-भिन्न प्रकार के बेल बूटे बनाती हैं। स्त्रियां पैरों में आलता भी लगाती हैं जो सुहाग का चिन्ह माना जाता है।

यह भारतीय परम्परा में पति पत्नी के प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने तथा आपस में श्रद्धाव और विश्वास पैदा करने का त्योहार है। इस दिन कुआंरी कन्याएं व्रत रखकर अपने लिए शिव जैसे वर की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग को भगवान शिव तथा पार्वती से अक्षुण्ण बनाए रखने की कामना करती हैं। इस तीज पर निम्न बातों को त्यागने का विधान है- पति से छल कपट, झूठ बोलना एवं दुर्व्यवहार, परनिन्दा। कहते हैं कि इस दिन गौरी विरहाग्नि में तपकर शिव से मिली थीं। इस दिन राजस्थान में राजपूत लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। माता पार्वती की सवारी निकाली जाती है। राजा सूरजमल के शासन काल में इस दिन कुछ पठान कुछ स्त्रियों का अपहरण करके ले गये थे, जिन्हें राजा सूरजमल ने छुड़वाकर अपना बलिदान दिया था। उसी दिन से यहां मल्लयुद्ध का रिवाज शुरू हो गया।

इस पर्व को बुन्देलखंड में हरियाली तीज के नाम से व्रतोत्सव के रूप में मनाते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे कजली तीज के रूप में मनाने की परम्परा है। राजस्थान के लोगों के लिए त्यौहार जीवन का सार है खासकर राजधानी जयपुर में इसकी अलग ही छटा देखने को मिलती है। यदि इस दिन वर्षा हो, तो इस पर्व का आनंद और बढ़ जाता है। राजस्थान सहित उत्तर भारत में नवविवाहिता युवतियों को सावन में ससुराल से मायके बुला लेने की परम्परा है। सभी विवाहिताएँ इस दिन विशेष रूप से श्रृंगार करती हैं। सायंकाल सज संवरकर सरोवर के किनारे उत्सव मनाती हैं और कजली गीत गाते हुए झूला झूलती हैं।

बताया जाता है कि जयपुर के राजाओं के समय में पार्वती जी की प्रतिमा, जिसे 'तीज माता' कहते हैं, को एक जुलूस उत्सव में दो दिन तक ले जाया जाता था। उत्सव से पहले प्रतिमा का पुनः रंगरोगन किया जाता है और नए परिधान तथा आभूषण पहनाए जाते हैं इसके बाद प्रतिमा को जुलूस में शामिल होने के लिए लाया जाता है। हजारों लोग इस दौरान माता के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते हैं। शुभ मुहूर्त में जुलूस निकाला जाता है। सुसज्जित हाथी और बैलगाड़ियां इस जुलूस की शोभा को बढ़ा देते हैं।

अगस्त के महीने में पड़ रही दो एकादशी तिथियां, यहां देखिए डेट और मुहूर्त

हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने दो एकादशी तिथियां होती हैं। इसी तरह अगस्त के महीने में भी दो एकादशी पड़ रही हैं। जिनमें पहली सावन पुत्रदा एकादशी और दूसरी अजा एकादशी है।

नई दिल्ली। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने दो एकादशी तिथियां होती हैं, जिनमें अलग-अलग तरीके से पूजन किया जाता है। वहीं सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी पड़ती है।

जो भी जातक पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसको संतान प्राप्ति होती है और संतान की सेहत अच्छी रहती है। इसी तरह अगस्त के महीने में भी दो एकादशी तिथियां पड़ रही हैं। जिनमें पहली सावन पुत्रदा एकादशी और दूसरी अजा एकादशी है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस महीने पड़ने वाली दोनों तिथियों के शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में बताने जा रहे हैं।

कब है पुत्रदा एकादशी

हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि जो भी जातक इस दिन विधि-विधान से श्रीहरि की पूजा-अर्चना करता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आमतौर पर सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अगस्त के महीने में पड़ती है।

शुभ मुहूर्त

सावन पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरूआत- 15 अगस्त सुबह 10:26 मिनट से होगा

सावन पुत्रदा एकादशी तिथि की समाप्ति- 16 अगस्त सुबह 09:39 तक

उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी।

महत्व

सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का रक्षक और संरक्षक माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप दूर होते हैं और व्यक्ति जीवन-मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। बता दें कि यह व्रत एकादशी की पूर्व संध्या से शुरू होता है और अगले दिन यानी की द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है।

पूजा विधि

इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें।

इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन करें।

इस दिन भगवान श्रीहरि के मंत्र 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' का कम से कम 1 माला जाप करें।

सावन पुत्रदा एकादशी को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले फूल और पीला भोग अर्पित करें।

एकादशी कथा का पाठ करें।

आखिरी में आरती करें और जरूरदमंदों व गरीबों को दान करें।

कब है अजा एकादशी

इस बार 29 अगस्त 2024 को अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार, इस एकादशी का व्रत करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त

अजा एकादशी तिथि की शुरूआत- 29 अगस्त 2024, गुरूवार सुबह 01:18 बजे से

एकादशी तिथि की समाप्ति- 30 अगस्त 2024, शुक्रवार सुबह 01:36 बजे तक

व्रत पारण का शुभ मुहूर्त- 30 अगस्त, 2024, सुबह 08:44 बजे से दोपहर 11:12 बजे तक

अजा एकादशी का महत्व

बता दें कि हिंदू धर्म में भादो माह के कृष्ण पक्षी में पड़ने वाली अजा एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस दिन श्रीहरि के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार, इस एकादशी का व्रत करने से जातक को अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को कई यज्ञों के करने के बराबर फल मिलता है।

अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी को व्रत करता है और विधि-विधान से श्रीहरि की पूजा-अर्चना करता है, उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत को करने से आध्यात्मिक उन्नति और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है।

अजा एकादशी पूजा विधि

इस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि कर पूजा स्थल को साफ कर लें।

फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें और लकड़ी की चौकी पर उनकी प्रतिमा स्थापित करें।

इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और पूरे परिवार के साथ बैठकर पूजा करें।

पूरा दिन व्रत करें और फिर शाम को श्रीहरि विष्णु की पूजा करें।

व्रत में आप फलाहार कर सकते है और भोग में भी फलाहार अर्पित करें।

इस दिन भगवान विष्णु को पीली वस्तुओं का भोग लगाना शुभ माना जाता है।

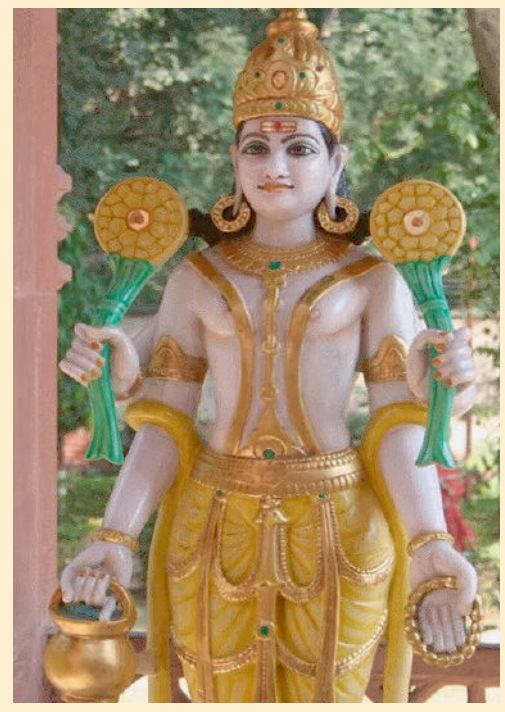

इन लोगों को भूलकर भी चीया सीड्स नहीं खाना चाहिए? हो जाएगी परेशानी

नई दिल्ली। चीया सीड्स खाने से शरीर को काफी फायदा कर सकता है। इससे आप खुद को कई छोटी-बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में चिया सीड्स खाना नुकसान हो सकता है। चीया सीड्स वजन घटाने में सहायक है। चीया सीड्स में कई पोशक तत्व पाए जाते हैं जो खतरनाक बीमारियों से भी छुटकारा देता है। चीया सीड्स के लिए काफी फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं किन लोगों को चीया सीड्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

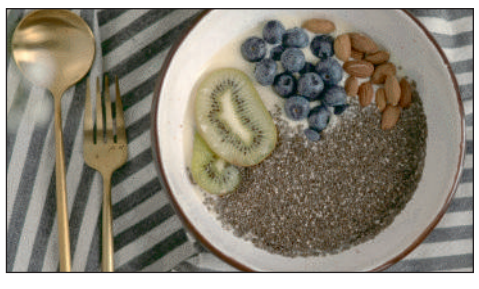

चीया सीड्स फायदेमंद क्यों है?

चीया सीड्स सेहत के लिए सबसे फायदेमंद होते हैं। चीया सीड्स में कैंसर-रोधी और एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने में मदद करता है। चीया सीड्स स्किन और बालों के लिए फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन-बी1, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फैट, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस और एंटी-ऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व होते हैं। हालांकि, इन लोगों को नहीं खाना चाहिए चीया सीड्स।

पाचन- तंत्र कमजोर होने पर न खाएं

जिन लोगों को पाचन संबंधित परेशानियां होती हैं, उन लोगों को चीया सीड्स का सेवन नहीं करना चाहिए। चीया सीड्स में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जिसे शरीर पचा नहीं पाता है।

डायबिटीज के मरीज न खाएं

डायबिटीज मरीजों को चीया सीड्स का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे ब्लड शुगर लेवल ज्यादा लो हो सकता है। चिया सीड्स में फाइबर होता और यह ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करता है। इससे लो शुगर वालों की समस्या बढ़ सकती है।

ब्लड प्रेशर के मरीज न खाएं

अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो चीया सीड्स का सेवन न करें। इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड में खून पतला करने वाला गुण पाया जाता है। इससे ब्लड प्रेशर काफी लो हो सकता है।

एलर्जी से जूझ रहे लोग न खाएं

यदि आपको स्किन एलर्जी है तो चीया सीड्स का सेवन न करें। ऐसा करने से आपको काफी नुकसान हो सकता है।

एक्ट्रेस जैसा फेस ग्लो पाने के लिए इन हाइलाइटर्स का करें यूज, मिलेगी ग्लोइंग ग्लास स्किन

हाइलाइटर को गालों, आंखों के किनारों और नाक के ऊपर हल्का सा हाइलाइट किया जाता है। इन दिनों हाइलाइटर में गोल्डन, ब्रॉन्ज और पिंक शेड फैशन में हैं। इनको अलग-अलग स्किन टोन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है।

नई दिल्ली। मेकअप करना हर महिला व लड़की को पसंद होता है। वहीं दमकते चेहरे के लिए हाइलाइटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइलाइटर के बिना मेकअप अधूरा लगता है। बता दें कि लेटेस्ट ब्यूटी ट्रेंड में हाइलाइटर काफी ज्यादा पॉपुलर है। हाइलाइटर को गालों, आंखों के किनारों और नाक के ऊपर हल्का सा हाइलाइट किया जाता है।

इन दिनों हाइलाइटर में गोल्डन, ब्रॉन्ज और पिंक शेड फैशन में हैं। इनको अलग-अलग स्किन टोन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो लिक्विड या फिर पाउडर में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रही हैं, तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ बेस्ट हाइलाइटर के बारे में बताने जा रहे हैं।

Lakme हाइलाइटर

यह हाइलाइटर क्रीम टू पाउडर फिनिश और केवल एक स्वाइप में आपको पर्फेक्शन देता है। इसमें विटामिन ई और जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। इसको अप्लाई करने से फेस पर लाइट रिफ्लेक्टिंग शाइन पिगमेंट्स नजर आते हैं। साथ ही यह त्वचा में एंटी एजिंग इफेक्ट भी लाता है।

मेकअप रिवॉल्यूशन हाइलाइटर

यह हाइलाइटर आसानी से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है। यह आपकी त्वचा को स्मूदनेस देता है और यह लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूले के साथ आता है। इसको फेस पर अप्लाई करने से आपको शिमरी और सिल्की इफेक्ट मिलता है। यह आपके फेस के ऑयल को कंट्रोल कर बैलेंस्ड ग्लो देता है। इसको लगाने से त्वचा सॉफ्ट लगती है और इसमें हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

सुगर कॉस्मेटिक हाइलाइटर

यह हाइलाइटर लॉन्ग लास्टिंग और लाइटवेट इफेक्ट देने का काम करता है। यह आपके चेहरे की त्वचा को रॉयल रोज टच देता है। इसको अप्लाई करने से शिमरी फिनिस ग्लो मिलता है। बता दें कि इसको फाउंडेशन के ऊपर या फिर पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्टिक से आप इसको आसानी से इस्तेमाल में ला सकती हैं।

LAMIOR हाइलाइटर

LAMIOR के इस इल्युमिनेटर से ग्लास स्किन वाला ग्लो मिलता है। यह आपको ड्यूवी फिनिश देने का काम करता है। यह वाटरमेलन, चैमोमाइल और नियासिनअमाइड के साथ मिलकर हाईब्रिड रोल निभाता है। इसमें हैलो शेड्स के साथ 6 और शेड्स मिलते हैं। ऐसे में आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से इसको आसानी से चूज कर सकती हैं।

इसका उपयोग कैसे करें और यह क्या कर सकता है?

मेटा एआई, कंपनी चैटजीपीटी जैसा एआई चैटबॉट अब इंस्टाग्राम के डीएम टैब में रहता है। इसका उपयोग कैसे करें यहां बताया गया है।

नई दिल्ली। कुछ महीने पहले मेटा ने भारत में मेटा एआई अपने चैटजीपीटी जैसे एआई संचालित चैटबॉट को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर में एकीकृत करना शुरू किया था। कंपनी का कहना है कि नए टेक्स्ट-आधारित अनुभव लामा 2 द्वारा संचालित हैं, लेकिन यह फोटो निर्माण क्षमताओं के लिए लामा 3 का उपयोग कर रहा है।

व्हाट्सएप की तरह, इंस्टाग्राम पर मेटा एआई को मुख्य स्क्रीन से दाईं ओर स्वाइप करके और ऐप के डीएम सेक्शन में शीर्ष सर्च बार पर टैप करके एक्सेस किया जा सकता है। एक बार जब आप मेटा एआई खोलते हैं, तो आप या तो चैटबॉट से अपनी पसंद का प्रश्न पूछ सकते हैं या कुछ पूर्व-लिखित संकेतों पर टैप कर सकते हैं। एक बार चैटबॉट के साथ बातचीत शुरू होने पर, यह आपके संदेशों के अंतर्गत दिखाई देगी।

मेटा AI इंस्टाग्राम पर क्या कर सकता है?

लामा 2 और लामा 3 बड़े भाषा मॉडल के संयोजन द्वारा संचालित, मेटा एआई आपको शुरुआत से स्टिकर बनाने, ड्राफ्ट कैप्शन में मदद करने, संदेश लिखने, चित्र बनाने, यात्राओं की योजना बनाने, लंबे पैराग्राफ को सारांशित करने जैसे कई कार्यों में मदद कर सकता है। पाठ का विवरण और यहां तक कि आपको नवीनतम समाचार सुर्खियां प्राप्त करने में भी मदद करता है।

हालांकि, जैसा कि ChatGPT, जेमिनी जैसे AI चैटबॉट्स और Perplexity जैसे AI संचालित सर्च इंजनों के मामले में होता है, मेटा AI कभी-कभी गलत हो सकता है और मति भ्रम का खतरा होता है। और जब आप मेटा एआई द्वारा उत्पन्न छवियों को संशोधित कर सकते हैं, जो DALL-E संचालित Microsoft डिजाइनर के बराबर हैं, तो कभी-कभी उत्पन्न छवि आपके संकेत के समान नहीं हो सकती है।

गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण, ऐसा लगता है कि मेटा ने अपने एआई चैटबॉट को व्यक्तिगत बातचीत तक पहुंच नहीं दी है, लेकिन आप मेटा एआई का उपयोग अपने व्यक्तिगत संदेश को फिर से लिखने, छोटा करने, लंबा करने या मजेदार या अधिक सहायक बनाने या उसमें इमोजी जोड़ने के लिए कर सकते हैं। यदि आप किसी से बात करते समय मेटा एआई का उपयोग करना चाहते हैं, तो अपने लिखित टेक्स्ट को संशोधित करने के लिए टेक्स्ट बार के बाईं ओर पेंसिल जैसे बटन पर टैप करें।

चैटजीपीटी, कोपायलट और जेमिनी की तरह, इंस्टाग्राम पर मेटा एआई भी यात्राओं की योजना बनाने, आपके सामने आने वाले व्यंजनों की रेसिपी प्राप्त करने में काम आ सकता है, लेकिन यह इन लोकप्रिय चैटबॉट्स की तरह फाइलों का विश्लेषण नहीं कर सकता है।

गंदे से गंदे काले पड़े गैस बर्नर होंगे साफ, बस अजमाएं ये टिप्स

अगर आपके भी किचन के गैस बर्नर ज्यादा ही गंदे हैं तो इस हैक्स के जरिए साफ करें। इस ट्रिक कम मदद से गंदे से गंदे गैस बर्नर भी साफ हो जाएंगे।

जब हम सभी किचन की सफाई करते हैं तो गैस के बर्नर को साफ करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में परेशान होते हैं कैसे साफ करें। लेकिन कई बार ये साफ होने के बाद भी गंदे ही दिखते हैं। अगर लंबे समय तक गैस बर्नर साफ न करें तो उनके छेदों में गंदगी जमने लगती है और ये मेल से काले भी दिखने लगते है। जिस कारण कई बार गैस से आग सही नहीं निकलती और गैस लीक होने का खतरा भी बना रहता है। वैसे तो इसे साफ करने में ज्यादा समय लगता है लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से मिनटों में होगा साफ।

सिरका का यूज

बर्नर को साफ करने के लिए आप सिरेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस का प्रयोग से बर्नर अच्छे से साफ होगा। सबसे पहले एक कटोरी में सिरका और नमक डालकर मिक्स करके उबाल लें। इस पानी में गंदे गैस के बर्नर डालकर कुछ देर के लिए रख दें। इस उपाय के बाद गंदे बर्नर जैसे चमक जाएंगे।

ईनो का इस्तेमाल

गैस बर्नर साफ करने के लिए आप इस टिप्स को जरुर फॉलो करें। आपको एक कटोरी गर्म पानी लेकर उसमें नींबू और इनो को मिक्स करके इस लिक्विड को बर्नर पर कुछ देर डालकर छोड देना है। इसके बाद लिक्विड को साफ करके ब्रेश की मदद से साफ करके साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से सूखा लें।

नींबू का यूज करें

गंदे गैस बर्नर को साफ करने के लिए नींबू का यह उपाय कर सकते है। इस उपाय को फॉलो करने के लिए एक बाउल में गर्म पानी लेकर उसमें रात भर के लिए बर्नर को डूबा दीजिए। अगली सुबह नींबू के छिलके में नमक लगाकर बर्नर की सफाई करें। इस किचन हैक्स को फॉलो करने से गैस बर्नर नए की तरह चमकने लगेगा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव : दिल्ली में फरवरी से पहले होंगे चुनाव? क्यों लगाई जा रहीं अटकलें

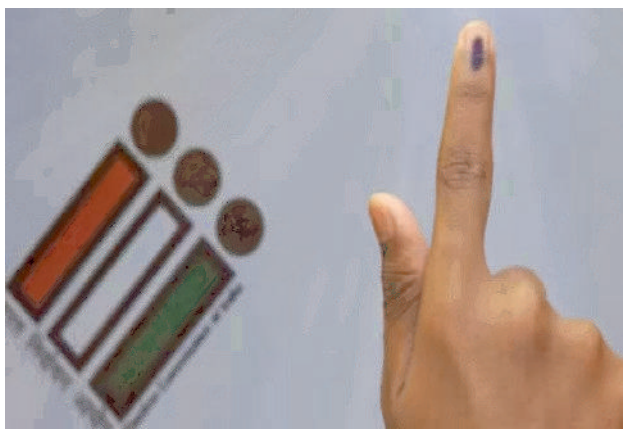

सुषमा रानी

दिल्ली में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। यह अटकलें दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के एक पत्र के बाद लगाई जा रही हैं। उन्होंने सरकारी कार्यालयों से स्टाफ की जानकारी मांगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी में प्रस्तावित हैं लेकिन इस बार चुनाव की अटकलें जल्दी होने की लगाई जा रही हैं। पार्टियां तो पहले ही तैयारी में जुटी हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सत्ताधारी पार्टी आप, कांग्रेस और भाजपा अपनी तैयारियों में लगी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के पांच साल फरवरी माह में हो रहे हैं। इस बार चुनाव जल्दी हो सकते हैं। इन अटकलों को हवा तब और ज्यादा मिली जब, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने एक पत्र लिखा।

सीईओ कार्यालय ने मंगलवार को पत्र भेजकर दिल्ली सरकार के सभी प्रमुख विभागों से स्टाफ की जानकारी मांगी है। जिसमें सभी प्रमुख विभागों से सात दिन के अंदर स्टाफ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।

हरियाणा के साथ चुनाव की संभावना

अधिकारियों में इस बात की सुगबुगाहट है कि चुनाव से तीन से चार माह पहले पूरी की जाने वाली प्रक्रिया शुरू होने का मतलब साफ है कि दिल्ली में भी हरियाणा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।

फरवरी में होते हैं चुनाव

बता दें कि दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। वर्तमान सरकार ने 2020 के फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में शपथ ली थी। दिल्ली की राजनीति में यह बात पिछले दो माह से घूम रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी से पहले हो सकते हैं।

हालांकि इस बारे में किसी राजनीजिक दल या अन्य किसी की ओर से बयान नहीं आया है। दिल्ली पत्र मिलने पर सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव को लेकर तो कोई संकेत नहीं हैं, मगर यह बात सही है कि चुनाव को लेकर स्टाफ के बारे में तीन से चार माह पहले जानकारी मांगी जाती है।

दिल्ली में फिलहाल आप सरकार

दिल्ली की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो दिल्ली में इस समय आप की सरकार है। पिछली दो बार आप पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। 2015 में आप ने 70 में से 67 सीटें जीती थीं और फरवरी 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आप ने 62 सीटें जीती थीं।

एक कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद मंत्री और पार्टी से इस्तीफा देने तथा छतरपुर से विधायक करतार सिंह द्वारा विधायक पद से इस्तीफा दे देने के बाद भी आप के पास इस समय 60 विधायक हैं।

बारिश के बाद दिल्ली में बढ़ें डेंगू के मामले, बच्चे बीमार

बारिश के बाद दिल्ली में डेंगू के मामले में बढ़ने लगे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों फिर युवाओं पर दिख रहा है। अस्पतालों में डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। लाई के महीने से डेंगू के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है क्योंकि वर्षा का यह पीक सीजन होता है। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति के शरीर की प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती हैं।

नई दिल्ली। मानसून में वर्षा की शुरुआत होने के साथ ही डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली के बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान में डेंगू के रोजाना करीबन चार-पांच मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 40 से अधिक लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं।

संस्थान में डेंगू के मामले सामने आ रहे इसके लिए एक हफ्ते में अलग से ओपीडी की भी शुरुआत की जाएगी। डॉक्टर्स का कहना है कि जुलाई के महीने से डेंगू के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, क्योंकि वर्षा का यह पीक सीजन होता है।

बच्चे और युवा ज्यादा पीड़ित

हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चों और नौजवानों में अधिक डेंगू के केस निकल रहे हैं। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति के शरीर की प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती हैं। इसलिए इस मौसम में घर या बाहर किसी भी जगह पर पानी भरने न दें इसका बेहद ख्याल रखें।

25 जुलाई के बाद बढ़े मरीज

नजफगढ़ के खैरा डाबर स्थित चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान में 21 ओपीडी हैं, जहां पर रोजाना 1,500 मरीज इलाज के लिए आते हैं। आयुर्वेद संस्थान में डेंगू के रोजाना चार-पांच मरीज आ रहे हैं, जिनकी जांच करने के बाद उन्हें दवा दी जा रही है। वहीं, उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गौरव ने बताया कि डेंगू के मरीजों की संख्या में 25 जुलाई के बाद से बढ़ोत्तरी देखी गई है। चार से पांच डेंगू के मरीज रोजाना आ रहे हैं।

पिछले 10 दिनों में 40 से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है। बच्चों में डेंगू के अधिक केस निकल रहे हैं। साथ ही 20 से 30 वर्ष के नौजवान भी ग्रस्त हो रहे हैं।

मरीजों की जांच करने के बाद उन्हें दवा के साथ ही काढ़ा भी दिया जाता है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स तेजी के साथ गिरती हैं जिन्हें रोकना जरूरी होती है। अगर किसी व्यक्ति की 20,000 तक प्लेटलेट्स पहुंची जाती हैं तो ऐसी स्थिति में मरीज गंभीर हालत में माना जाता है।

आयुर्वेद से एक हफ्ते में ठीक होता है डेंगू

उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गौरव बताते हैं कि डेंगू का बुखार आयुर्वेद दवा से तीन दिन में उतर जाता है। आयुर्वेद की दवा बीमारी को जड़ से खत्म करती है। कोई भी बीमारी हो उसे जाने में थोड़ा समय लगता है। डेंगू का तरीके से नियमित इलाज हो तो व्यक्ति आयुर्वेद से अधिकतम एक हफ्ते में ठीक हो जाता है।

डेंगू के बुखार में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर बुखार एक से दो दिन में नहीं उतरता तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

जल्द शुरू होगी डेंगू की अलग से ओपीडी

आयुर्वेद संस्थान के निदेशक एमबी गौड़ ने बताया कि डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसको लेकर हमारी तैयार पूरी है। एक हफ्ते के अंदर डेंगू के लिए अलग से ओपीडी शुरू की जाएगी, ताकि डेंगू से पीड़ित व्यक्ति का घंटों समय बर्बाद न हो। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद से इलाज कराने पर व्यक्ति को कभी भी साइडइफेक्ट नहीं होते हैं।

डेंगू से ऐसे करें बचाव

घर के अंदर या बाहर वर्षा का पानी एकत्र न होने दें।

बच्चे घर के बाहर पूरी बाजू के कपड़े पहनकर निकलें।

घर की टंकियों को नियमित साफ करते रहें।

बच्चों को पार्क में भेजने से बचें।

एल्डरमैन नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, AAP सरकार ने जताई असहमति तो बोले LG- आत्ममंथन की जरूरत

दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनिवास ने कहा कि आप सरकार को आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। राजनिवास ने कहा कि सरकार ने केवल शीर्ष अदालत का समय बर्बाद किया है। साथ ही कहा कि आप सरकार ने एमसीडी को जानबूझकर पंगु बना दिया। पढ़िए और क्या कहा है?

नई दिल्ली। राजनिवास ने बुधवार को कहा कि एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप सरकार के लिए "आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण" की जरूरत जताता है। इसके साथ ही राजनिवास ने उम्मीद जताई कि अब नगर निगम में स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया में तेजी देखने को मिलेगी।

राजनिवास ने बुधवार शाम को एक बयान में दिल्ली सरकार पर ₹व्यर्थ मुकदमेबाजी₹ में शामिल होने का आरोप लगाते हुए, कहा कि सरकार ने न केवल शीर्ष अदालत का समय बर्बाद किया, बल्कि एमसीडी को ₹जानबूझकर₹ पंगु बना दिया।

बयान में कहा गया है, ₹यह फैसला सत्तासीन सरकार और उसके नेताओं को आत्मावलोकन और आत्मनिरीक्षण का आह्वान करता है। जनहित सर्वोपरि है और इसे मैदानी लड़ाई की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता है।₹

सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में 10 'एल्डरमैन' नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 'एल्डरमैन' नामित करने के एलजी के फैसले को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति।

इससे पहले दिल्ली में एमसीडी के पार्षदों की नियुक्ति का फैसला बिना अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रियों से विचार-विमर्श कर किए जाने का आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने विरोध किया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के इस फैसले पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पार्डीवाला ने पिछले साल 17 मई को सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

आईजीएल पाइपलाइन में लगी आग, मकानों में फैली लपटें; दो बाइक जलकर हुई राख

राजधानी दिल्ली में कालकाजी के ए-वन ब्लाक में केबल की वेल्डिंग करने के दौरान आईजीएल पाइपलाइन में आग लग गई। बताया गया कि बीएसईएस कर्मियों की लापरवाही से आग लगी है। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि कई मकानों में लपटें फैल गईं जिससे मकानों के दरवाजों का कांच टूट गया। दो बाइक भी जलकर राख हो गई।

नई दिल्ली। कालकाजी के ए-वन ब्लाक में बुधवार को बीएसईएस कर्मियों की लापरवाही से आईजीएल पाइपलाइन में आग लग गई। आग उस समय लगी, जब बीएसईएस कर्मी खुदाई कर केबल की वेल्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान आईजीएल की पाइपलाइन लीक हो गई, जिससे तुरंत आग लग गई।

वहीं, आसपास के चार घरों में भी आग की लपटें फैल गईं। जिससे मकानों की खिड़की, दरवाजों के कांच टूटने के साथ ही एसी और बाहर खड़ी दो बाइक जलकर खाक हो गई।

दिल्ली में मकान का छज्जा गिरने से बुजुर्ग दंपती की मौत, मलबे से निकाले दोनों के शव

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में एक मकान का छज्जा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और शवों को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस मकान में रहने वालों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं मलबा हटाने का काम भी जारी है।

नई दिल्ली। प्रेम नगर थाना क्षेत्र स्थित एक जर्जर मकान का छज्जा मंगलवार देर रात गिरने से छज्जे के नीचे सो रहे बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हो गया। पड़ोसियों ने आनन-फानन घायलों को मलबे से निकालकर मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने बुजुर्ग दंपती को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल बेटे को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। मृतकों की पहचान 85 वर्षीय सुखराम सिंह व इनकी पत्नी 75 वर्षीय गायत्री देवी के रूप में हुई है। बेटे की पहचान 40 वर्षीय विनोद उर्फ कल्लू के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक मकान जर्जर होने की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस घायल बेटे व पड़ोसियों से पूछताछ के आधार मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

दो बेटों के साथ रहता था दंपती

जानकारी के अनुसार, सुखराम अपने परिवार के साथ प्रेम नगर स्थित जे-बलाक, गली नंबर-3 में 25 गज के मकान में पत्नी गायत्री देवी व दो बेटे विनोद और पंकज के साथ रहते थे। विनोद व पंकज नौकरी कर परिवार का गुजारा करते थे। मकान काफी जर्जर हालत में था। उसकी छत और छज्जा टुकड़ी-टी-आयरन का बना हुआ था।

छज्जे के नीचे सो रहे थे दंपती

मंगलवार की रात बुजुर्ग दंपती और विनोद कमरे के बाहर छज्जे के नीचे सो रहे थे। जबकि सुखराम का दूसरा बेटा पंकज कमरे में सो रहा था। रात करीब 02:57 बजे अचानक छज्जा नीचे सो रहे दंपती व उनके बेटे विनोद के ऊपर गिर पड़ा। सभी मलबे में दब गए। कमरे में सो रहा पंकज तुरंत बाहर निकल, पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाने लगा।

पड़ोसियों की मदद से सभी को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बुधवार को संजय गांधी अस्पताल में पोस्मार्टम के बाद दंपती का शव उनके बेटों को सौंप दिया।

आर्थिक रूप से कमजोर था परिवार

मृतक के बेटे पंकज ने बताया वह और उनका भाई विनोद मेहनत-मजदूरी कर घर चलाते थे। जिससे केवल घर का ही खर्च निकाल पाते थे। थोड़े से पैसे बचाते भी थे, तो बुजुर्ग माता-पिता के इलाज में खर्च हो जाता था। वे चाहकर भी घर की मरम्मत नहीं करा पाते थे।

आए दिन मकान की मरम्मत को लेकर आपस में बात तो होती थी, लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे कि इसकी मरम्मत कराई जाए। बस इंतजार में समय बीतता गया और मकान भी जर्जर होता चला गया।

पड़ोसियों ने भी बताया कि काफी समय से मकान की मरम्मत नहीं हुई, जिससे की यह जर्जर छज्जा नीचे सो रहे दंपती के ऊपर गिरा और जिससे की उनकी मौत हो गई।

गर्लफ्रेंड की विश पूरी करने के लिए घर का लुटेरा बन गया नाबालिग, मां के गहने बेचकर खरीदा आईफोन

गर्लफ्रेंड को जन्मदिन पर आईफोन का तोहफा देने के लिए नाबालिग ने मां के आभूषण चुरा लिए। वह जेवरात को बेचकर आईफोन खरीदकर गिफ्ट करना चाहता था। मां को पहले इस बारे में कुछ नहीं पता था। चोरी के बाद से बेटा फरार चल रहा था। मां ने थाने में जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पश्चिमी दिल्ली। नजफगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में अपनी ही मां के जेवरात चुरा लिए, क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर उसे एक आईफोन गिफ्ट करना चाहता था। नाबालिग आरोपी ने आईफोन खरीद भी लिया। लेकिन जल्द ही उसका राज खुल गया।

पुलिस ने नाबालिग और जेवरात खरीदने वाले एक आभूषण कारोबारी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी आभूषण कारोबारी का नाम कमल वर्मा है। पुलिस ने नाबालिग व आभूषण कारोबारी के पास से आईफोन और बेचे गए जेवरात बरामद कर लिए हैं। नाबालिग नौवीं कक्षा का छात्र है।

महिला ने थाने दर्ज कराई चोरी की शिकायत

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि तीन अगस्त को एक महिला ने अपने घर में चोरी की शिकायत नजफगढ़ थाना पुलिस को दी थी। पीड़िता ने बताया कि किसी ने दो अगस्त को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे के बीच घर में रखे लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर लिए।

वारदात के बाद से गायब था नाबालिग बेटा

नजफगढ़ थाना पुलिस ने प्राथमिकी कर छानबीन शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। घटना के समय पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि वारदात के बाद से महिला का नाबालिग बेटा गायब है।

स्कूल के छात्रों से आईफोन का चला पता

पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस बीच पुलिस ने पीड़ित पक्ष के स्वजन, पड़ोसियों व नाबालिग के स्कूल के छात्रों से पूछताछ की तो पता चला कि नाबालिग ने एक-दो दिन पहले महंगा आईफोन खरीदा है। पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया। नाबालिग की तलाश के लिए धर्मपुरा, ककरोला, नजफगढ़ के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की गई।

पांच लाख श्लोकों वाले "महाभारत" का सार मात्र नौ पंक्तियो में समझें:

परिवहन विशेष न्यूज

चाहे आप हिंदू हो या किसी अन्य धर्म से...

चाहे आप महिला हो या पुरुष...

चाहे आप गरीब हो या अमीर...

चाहे आप अपने देश में हो या विदेश में...

अगर आप एक इंसान है तो नीचे दिए गए महाभारत के "9 अनमोल लेशन" को पढ़ें और समझें:

1. अगर आप समय रहते अपने बच्चों की अनुचित मांगो और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते है तो आप जीवन में असहाय हो जाएंगे...!

-"कौरव"

2. आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आप अधर्म का साथ देंगे तो आपकी ताकत, हथियार, कौशल और आशीर्वाद सब बेकार हो जाएंगे...!

- "कर्ण"

3. अपने बच्चों को इतना महत्वाकांक्षी न बनाएं कि वे अपने ज्ञान का दुरुपयोग करें और कुल विनाश का कारण बनें...!

- "अश्वत्थामा"

4. कभी भी ऐसे वादे न करें कि आपको अधर्मियों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़े...!

- "भीष्म पितामह"

5. धन, शक्ति, अधिकार का दुरुपयोग और गलत काम करने वालों का समर्थन अंततः पूर्ण विनाश की ओर ले जाता है...!

- "दुर्योधन"

6. सत्ता की बागडोर कभी भी किसी अंधे व्यक्ति को न सौंपें। अर्थात जो स्वार्थ, धन, अभिमान, ज्ञान, आसक्ति या वासना से अंधा हो, क्योंकि वह विनाश की ओर ले जाएगा...!

- "धृतराष्ट्र"

7. यदि ज्ञान के साथ बुद्धि भी हो, तो आप निश्चित रूप से विजयी होंगे...!

- "अर्जुन"

8. छल कपट आपको हर समय सभी मामलों में सफलता नहीं दिलाएगा...!

-"शकुनि"

9. यदि आप नैतिकता, धर्म और कर्तव्य को सफलतापूर्वक बनाए रखते है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती...!

- "युधिष्ठिर"

यह लेख सभी के लिए लाभदायक है, इसलिए कृपया इसे बिना किसी बदलाव के साझा करें।

"सर्वे भवन्तु सुखिनःसर्वे सन्तु निरामयाः"

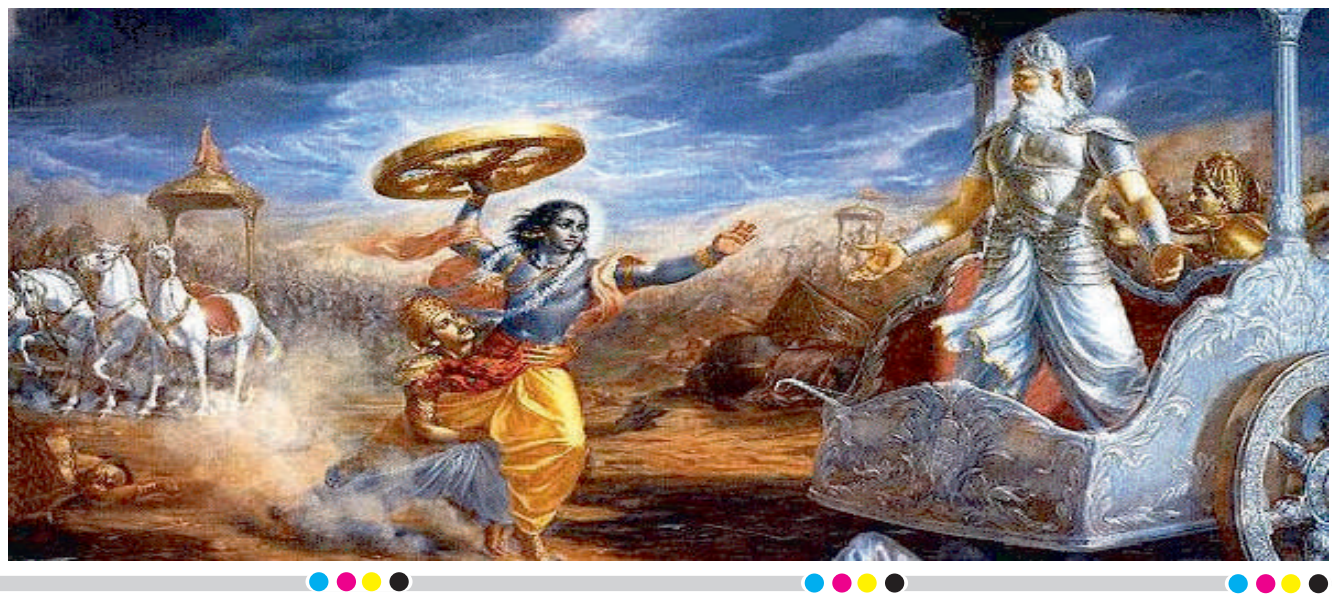

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसानी को लेकर हलचल, 48 घंटे से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात हैं पुलिसकर्मी

परिवहन विशेष न्यूज

हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर पिछले 48 घंटे से हलचल चल रही है। यहां 48 घंटे से ही पुलिसकर्मी तैनात हैं। बताया गया कि यहां से गुजरने वाले लोगों को शेख हसीना का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी ने शेख हसीना के अंदर होने की पुष्टि नहीं की है।

साहिबाबाद। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर सोमवार दोपहर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के पहुंचने को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। करीब 48 घंटे से स्टेशन के बाहर शेख हसीना को लेकर हलचल चल रही है।

स्टेशन के बाहर स्थानीय पुलिस व मीडियाकर्मी तैनात हैं। यहां से गुजर रहे लोग भी हसीना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि अंदर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है या नहीं। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हसीना के अंदर होने की कोई भी अधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है।

बांग्लादेश में शेख हसीना के विश्वासपात्रों ने भी छोड़ा देश

बांग्लादेश में हंगामे और अनिश्चितता के बीच शेख हसीना के विश्वासपात्र कई मंत्री देश छोड़ कर चले गए या छोड़ने की फिराक में हैं। इसके साथ ही कई मंत्रियों और वरिष्ठ अवामी लीग नेताओं के भागने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अवामी लीग सरकार में डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री रहे जुनैद अहमद पलक को मंगलवार को तब हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया है।

भारत आने की फिराक में कई नेता

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जुनैद अहमद पलक नई दिल्ली भागने की कोशिश कर रहे थे। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा कि तभी हवाई अड्डे के कर्मचारियों और श्रमिकों ने पूर्व मंत्री को दबोच लिया। इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हसीना की अवामी लीग के कई शीर्ष नेता और सांसद और कैबिनेट मंत्री उनके बांग्लादेश छोड़ने से पहले ही देश छोड़कर चले गए।

अवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन एवं पुल मंत्री ओबैदुल कादिर रविवार रात देश छोड़कर चले गए। उनके निजी सहयोगी ने कहा कि पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक हसीना के इस्तीफे से पहले देश छोड़कर अज्ञात स्थान पर चले गए।

हसीना के भतीजे शेख फजले सिंगापुर रवाना

उनके सहयोगियों के अनुसार, शेख हसीना के निजी उद्योग और निवेश सलाहकार और कानूनविद् सलमान एफ रहमान भी रविवार रात देश छोड़कर भाग गए, हालांकि, वे इस बात की जानकारी नहीं दी कि वह किस देश में जा रहे है। ढाका साउथ सिटी कारपोरेशन के मेयर और हसीना के भतीजे शेख फजले नूर तपोश शनिवार सुबह बिमान फ्लाइट से ढाका से रवाना हुए और विमानन सूत्रों ने बताया कि वह सिंगापुर जाने वाले विमान में सवार हुए।

मणिपाल अस्पताल के तीन चिकित्सकों के खिलाफ केस दर्ज, ऑपरेशन थियेटर में हुई थी युवती की मौत

परिवहन विशेष न्यूज

मणिपाल हॉस्पिटल में उपचार के दौरान युवती की मौत के मामले में तीन चिकित्सकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि युवती की रीढ़ की हड्डी में शिकायत बताकर भर्ती कराया गया था। इसके बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की जिससे युवती की मौत हो गई।

गाजियाबाद। मणिपाल अस्पताल में उपचार के दौरान युवती की मौत पर उसके पिता ने अस्पताल के चिकित्सकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि अस्पताल में गलत ऑपरेशन के कारण उनकी पुत्री की मौत हुई है।

प्रिया की रीढ़ की हड्डी में बताई थी परेशानी

विश्वास नगर में रहने वाले राजवीर सिंह ने बताया कि उनकी बेटी प्रिया वर्मा 18 अक्टूबर को मामूली परेशानी होने पर उपचार के एनएच- नौ पर लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंक सोसायटी के पास स्थित मणिपाल अस्पताल गई। वहां न्यूरोसर्जन डॉ. गजेंद्र सिंह सिंधू ने धन उगाही के उद्देश्य से प्रिया की रीढ़ की हड्डी में परेशानी बताई।

अक्टूबर 2023 का है मामला

इसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन के लिए उसको अस्पताल में भर्ती किया और गलत दवाएं देने और ऑपरेशन में लापरवाही के कारण प्रिया की तबीयत बिगड़ गई और ऑपरेशन थियेटर में ही उसकी मृत्यु हो गई।

तीन चिकित्सकों के खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट

आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉ. गजेंद्र सिंह सिंधू, डॉ. अजय शर्मा, डॉ. पवन कुमार व उनकी टीम ने लापरवाही की। जिनके पास अनुभव की कमी है। तीनों चिकित्सकों के खिलाफ शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में कूड़े से बनेगी बिजली, नहीं होगी गंदगी; नगर आयुक्त ने लोगों को दी अहम जानकारी

नगर आयुक्त ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हालांकि लोगों ने नगर आयुक्त के सामने अपने सुझाव भी रखे। लेकिन नगर आयुक्त ने कहा कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी और गंदगी भी नहीं होगी। पढ़िए और क्या-क्या जानकारी दी?

गाजियाबाद। गालंद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के निर्माण के संबंध में नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने गालंद पहुंच कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान विस्तार से चर्चा हुई। गांव के विकास कार्यों को लेकर भी ग्रामीणों ने सुझाव रखे।

ग्रामीणों को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बारे में बताया

नगर आयुक्त ने विस्तार से सभी ग्रामीणों को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बारे में बताया। मौके पर ही वीडियो चलाकर डेमो भी दिया गया कि गुजरात के जाम नगर मे बिना किसी परेशानी के कूड़े से बिजली बनाई जा रही है।

ग्रामीणों को नहीं होगी कोई दिक्कत

इस प्लांट में कूड़े से किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलेगी। प्लांट के निर्माण के दौरान भी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास होगा। किसी प्रकार की असुविधा ग्रामीणों को नहीं होगी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इसके अलावा प्लांट बनने से होने वाले अन्य लाभ के बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई संशय योजना को लेकर लोगों में नहीं रहना चाहिए।

ग्रामीणों ने नगर आयुक्त के सामने अपनी राय रखी

ग्रामीणों ने डंपिंग ग्राउंड बनने से गंदगी, बदबू का विषय रखा, जिस पर नगर आयुक्त ने उन्हें गुजरात, दिल्ली, इंदौर, गोवा में चल रहे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर विजिट करने के लिए सुझाव भी दिया, ताकि पूरी जानकारी लोगों को हो सके।

वहीं, मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने नगर आयुक्त के सुझाव का स्वागत करते हुए आपसी विचार विमर्श निर्णय लेने की बात कही।

आगामी योजना बनाते हुए जनहित में कार्य किया जाएगा

बातचीत के दौरान नगर आयुक्त ने ग्रामीणों को समझाया कि उक्त स्थान पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने की योजना है। गाजियाबाद नगर निगम की अपनी जमीन पर वर्तमान में केवल बाउंड्री का कार्य करेगा। इसके बाद आगामी योजना बनाते हुए जनहित में कार्य किया जाएगा।

इस दौरान अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार, उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज सिंह, जनकल्याण किसान वेलफेयर समिति के अध्यक्ष राजीव तोमर, बृजमोहन सिंह तोमर, हरिओम, प्रदीप, आकाश तोमर, सोनू, सत्येंद्र शर्मा व अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

अब आईटीआर भरने वाले किसानों को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, सरकार ने दिए आदेश

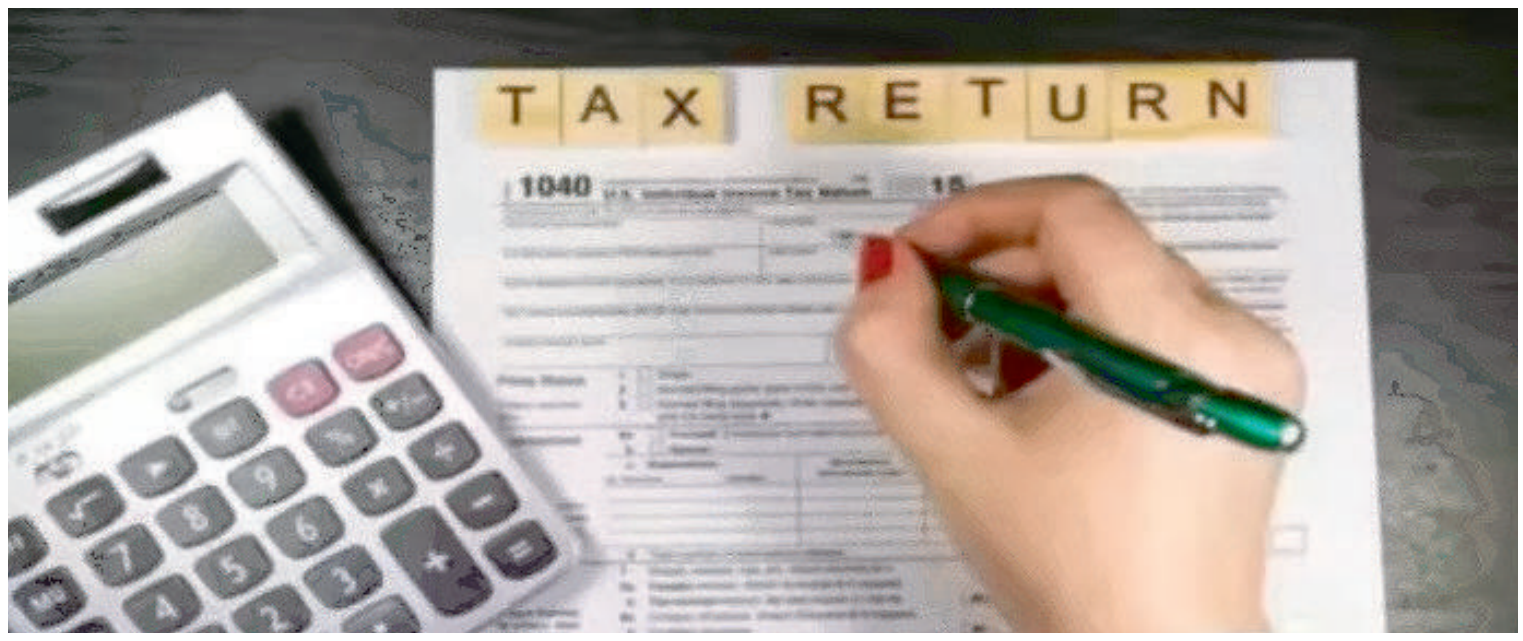

परिवहन विशेष न्यूज

PM Kisan Samman Nidhi अब जो किसान आयकर रिर्टन भरते हैं। उनके लिए जरूरी खबर है। यूपी सरकार अब उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दे रही है। इस योजना के तहत केंद्र द्वारा किसानों को एक साल में छह हजार रुपये उनके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं। गाजियाबाद जिले में 2 हजार किसान हैं। जिन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा है।

गाजियाबाद। अब आयकर रिर्टन भरने वाले किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। बशर्ते वह आयकरदाता न हों। केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी।

इसमें किसानों को एक साल में छह हजार रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा तीन किस्तों में किसानों के खाते में आता है। यानी हर किस्त को 4 महीनों के अंतराल पर केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है।

आयकर रिर्टन भरने वालों को मिले इस योजना का लाभ-सरकार

अभी हाल ही में सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में यह निर्देश जारी किए हैं कि जो किसान आयकर रिर्टन भरते हैं लेकिन वे आयकरदाता नहीं है तो उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाए।

सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि कई किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब उन्होंने इसकी जानकारी की तो पता चला कि वे आईटीआर भरते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मिलेगा लाभ

इस कारण उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है। इस तरह की कई शिकायतें आने पर सरकार ने उनका संज्ञान लिया। गाजियाबाद जिले की बात करें तो करीब दो हजार किसान ऐसे हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन तो किया लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

यह सभी किसान आईटीआर भरते हैं। इसके चलते इनके आवेदन को रोक दिया गया था। लेकिन सरकार के नए निर्देश आने के बाद कृषि विभाग अब ऐसे किसानों की पहचान करने में जुट गया है जो आईटीआर तो भरते हैं लेकिन आयकर दाता नहीं है। इनकी पहचान होने के बाद इन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा।

गाजियाबाद में करीब दो हजार किसान हैं जिन्होंने पीएम किसान निधि योजना में आवेदन किया था, लेकिन उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये सभी किसान आईटीआर भरते थे। अब इनमें उन किसानों की पहचान की जा रही है जो आयकर दाता नहीं है। इसके बाद उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।

बांग्लादेश के हालात से बहुत संतर्क रहना होगा

अशोक मधुप

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक के बावजूद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफे पर अड़े रहे। 14 जुलाई को बतौर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था, स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्या आरक्षण का लाभ रजाकारों के पोते-पोतियों को मिलेगा।

बांग्लादेश में महीनों से सुलग रही आरक्षण और सरकार विरोधी चिंगारी सोमवार को भीषण आग के रूप में फूटी। 300 लोगों की मौत के बाद सेना भी उग्र भीड़ को संभाल नहीं पाई। नतीजतन करीब डेढ़ दशक से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर देश से भागना पड़ा है। शेख हसीना भागकर फिलहाल भारत आई हैं। सूत्रों का कहना है कि शेख हसीना लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। शेख हसीना ने इंग्लैंड की सरकार से शरण मांगी है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन जारी है। अब प्रदर्शनकारियों ने देश के चीफ ऑफ जस्टिस के घर में घुसकर तोड़-फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने घर में मौजूद कार, फर्नीचर के साथ घर का सारा समान लूट ले गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला बोला। साथ ही काली व इस्कॉन समेत देशभर में कम से कम चार मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक डरे और सहमें हैं। वहां क्या हालात बनेंगे? वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी, इस पर भारत को नजर रखनी होगी। ये भी देखना है कि सरकार कैसी बनता है? उसका भारत के प्रति नजरिया कैसा होगा? नई सरकार कहीं इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा तो नही देगी। उसका रूख पाकिस्तान और चीन संमर्थक तो नहीं होगा? भारत को अपने देश की सीमा को पूरी तरह बंद रखना होगा, ताकि वहां के हालात से डरे नागरिक अपने भारत में न आ सकें।

1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों के परिवारों को सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण को खत्म करने की मांग के साथ पिछले महीने विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदर्शनकारी आखिर फिर से इतने हिंसक होकर सड़कों पर क्यों उतर आए। असल में हिंसा की यह नई लहर तब शुरू हुई जब प्रदर्शनकारियों ने असहयोग का आह्वान किया। इसमें लोगों से कर या बिजली बिल का भुगतान न करने और रविवार को काम पर न आने का आग्रह किया गया। सोमवार को जब कार्यालय, बैंक और कारखाने खुले, तो प्रदर्शनकारियों ने लोगों को काम पर जाने से रोकना शुरू कर दिया। सेना ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले लगाए गए कर्फ्यू की परवाह किए बिना ढाका में प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के शाहबाग इलाके में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी पर हमला किया है। प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों व वाहनों में भी आग लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक के बावजूद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफे पर अड़े रहे। 14 जुलाई को बतौर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था, स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्या आरक्षण का लाभ रजाकारों के पोते-पोतियों को मिलेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस बयान के बाद, 'तुई के, अमी के रजाकार, रजाकार' के नारे लगाने शुरू कर दिए और हिंसा ज्यादा भड़क गई।

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा गठित रजाकार क्रूर अर्धसैनिक बल था। रजाकारों ने मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों और आम लोगों के खिलाफ अत्याचार किया। आज भी यह शब्द वहां अपमानजनक माना जाता है। इसका इस्तेमाल देशद्रोहियों और अत्याचारियों के लिए किया जाता है।

बांग्लादेश में उथल-पुथल व तख्तापलट का इतिहास 1975 से शुरू होता है।हसीना के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों की हत्या कर दी गई। जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता पर कब्जा किया। 1981 गेस्ट हाउस में घुसकर विद्रोहियों ने जियाउर रहमान की हत्या की। हालांकि, सेना का बड़ा तबका वफादार होने से तख्तापलट नाकाम रहा। 1982 रहमान के उत्तराधिकारी अब्दुस सत्तार को हुसैन मुहम्मद इरशाद के नेतृत्व में सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इरशाद राष्ट्रपति बन गए। 2007 सेना प्रमुख ने एक कार्यवाहक सरकार का समर्थन किया, जो 2009 तक सत्ता पर काबिज रही। 2009 अर्धसैनिक बलों का विद्रोह.. में 70 लोगों की हत्या, इनमें से अधिकांश सैन्य अधिकारी थे।2012 सेना ने कहा, शरिया या इस्लामी कानून से प्रेरित तख्तापलट के प्रयास को विफल कर दिया है।

स्पष्टतौर पर बांग्लादेश में सुलग रही हिंसा के केंद्र में आरक्षण है। बांग्लादेश की जनसंख्या17 करोड़ है और देश में लगभग 3.2 करोड़ युवा बेरोजगार हैं।1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के वंशजों को मिल रहे आरक्षण को खत्म करने के लिए छात्र मांग कर रहे हैं। इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल रहे लोगों के वंशजों को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाता है। 10 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए भी है।

अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर पांच प्रतिशत व विकलांगों को एक फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़े जिलों में रहने वालों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है।बांग्लादेश में बेरोजगारी से परेशान युवक इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार, हसीना के रिश्ते में बहनोई हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार वहां सबसे अहम चेहरा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने ही शेख हसीना के देश छोड़कर जाने और इस्तीफे का एलान किया। 20 दिसंबर, 1985 को बांग्लादेश की सेना में शामिल हुए जनरल वकार की छवि एक बेहद अनुशासित अधिकारी की रही है। जानकारों का मानना है कि हसीना का बांग्लादेश छोड़कर जाना और वकार का कमान संभालना एक सोचा-समझा निर्णय है। शेख हसीना के देश छोडने के बाद देश के सेना प्रमुख ने कहा है कि वो सभी से बातचीत करके देश में अंतरिम सरकार बनवाएंगे! बांग्लादेश में तख्तापलट से पहले सत्तारूढ़ रही आवामी लीग पार्टी ने आरोप लगाया है कि देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन के पीछे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का हाथ है। आवामी लीग के मुताबिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग दिखाती है कि विरोध-प्रदर्शनों के पीछे असल में छात्र नहीं, देश के मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल-बीएनपी और प्रतिबंधित संगठन- जमात-ए-इस्लामी की रणनीति है। इनका मकसद किसी भी तरह से देश की सत्ता हासिल करना है।

बांग्लादेश में देशव्यापी आंदोलन के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। देश के राष्ट्रपति ने कहा है कि संसद भंग कर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। राष्ट्रपति ने विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया है। खालिदा जिया विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख हैं और 1991-96 और 2001-06 के दौरान दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। राष्ट्रपति बोले- खालिदा जिया की रिहाई के बाद अंतरिम सरकार का गठन होगा।

बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी नेताओं ने सोमवार को छात्रों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद देश में पैदा हुए हालात में किसी को भी लूटने का मौका न मिले, और उनसे अपनी मांगें होने तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का आग्रह किया।

बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक हुई है। जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के पड़ोसी देश के हालात पर जानकारी दी है। देखना यह है कि बांग्ला देश में अब किसकी सरकार बनती है।उसका भारत के प्रति रूख कैसा होता है? नई सरकार भारत समर्थक होगी या कट्टर इस्लाम का रास्ता स्वीकार कर पाकिस्तान को अपना आका मानेगी।हालाकि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार शेख हसीना के नजदीकी और रिश्ते में बहनोई लगतें हैं। उनसे उम्मीद है कि बांग्ला देश शेख हसीना के पद चिंहों पर चलेगा, किंतु वहां के राष्ट्रपति का रूख अभी देखना होगा।उसी रूख के आधार पर भारत को अपनी नई नीति बनानी होगी।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

टाटा कर्व ईवी भारतीय बाजार में हुई लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

बुधवार, 07 अगस्त को टाटा मोटर्स ने कूपे एसयूवी सेगमेंट में टाटा कर्व ईवी को 17.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया गया हैं। इस कार को पांच वेरिएंट और पांच कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। साथ ही इसकी बुकिंग 12 अगस्त से शुरू करने की घोषणा की गई है।

यह भारतीय बाजार में पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कूपे कार है। इसमें 6 एयरबैग और ADAS समेत 60 से ज्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर्स होंगे। यह कार दो वर्जन ICE और EV में उपलब्ध होगी। देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स टाटा कर्व ईवी की लॉन्चिंग के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का विस्तार कर रही है। नेक्सन ईवी, टियागो ईवी, पंच ईवी और टिगोर ईवी जैसे मॉडलों के साथ टाटा मोटर्स ने पहले ही भारतीय ईवी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

टाटा कर्व की सबसे बड़ी खासियत इसकी माइलेज है। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर तक चलेगी।

कर्व ईवी की रेंज 585 किलोमीटर बताई गई है। कंपनी का कहना है कि यूजर असल जिंदगी में 400-425 किलोमीटर की रेंज की उम्मीद कर सकते हैं।

टाटा कर्व में 12.3 इंच की टचस्क्रीन, एसी के लिए टच कंट्रोल और पैनारॉमिक सनरूफ शामिल है। इसमें नेक्सन जैसा सेंटर कंसोल, ड्राइव मोड सिलेक्टर के साथ वायरलेस चार्जर और स्टार्ट-स्टॉप बटन जैसे फीचर्स शामिल हैं।

टाटा कर्व ईवी दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी। एक 45 kWh पैक है जिसकी रेंज 502 किलोमीटर है और दूसरा 55 kWh पैक है जिसकी रेंज 585 किलोमीटर बताई गई है।

टाटा कर्व ईवी में 18 इंच के व्हील और 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। इस कार में 500 लीटर का बूट स्पेस भी है।

टाटा कर्व ईवी 123 kWh मोटर से लैस होगी, जिससे केवल 8.6 सेकंड में टाटा कर्व 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होगी।

फाडा की रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल छोड़ ईवी पर फोकस कर रहे लोग

परिवहन विशेष न्यूज

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 55.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा जुलाई महीने का है। जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 55.2 फीसदी बढ़कर 1,79,038 यूनिट रही। मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक-दोपहिया वाहनों की बिक्री में 96 फीसदी की अच्छी बढ़ोतरी के कारण कुल बिक्री में इजाफा हुआ है। वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के बिक्री आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री 1,16,221 यूनिट थी।

इलेक्ट्रिक दोपगहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने 95.94 प्रतिशत बढ़कर 1,07,016 इकाई हो गई। जुलाई 2023 में यह संख्या 54,616 इकाई थी। वहीं, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री 18.18 प्रतिशत बढ़कर 63,667 इकाई हो गई। पिछले साल 2023 के जुलाई महीने में यह 58,873 इकाई थी।

फाडा के आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन महीने में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री दोगुनी से अधिक होकर 816 इकाई हो गई। पिछले साल जुलाई में 364 वाणिज्यिक वाहन बिके थे। हालांकि, जुलाई में यात्री वाहनों की बिक्री 2.92 प्रतिशत घटकर 7,541 इकाई रह गई। जुलाई 2023 में यह 7,768 इकाई थी।

फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा कि दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खंड में बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है। जुलाई में साल-दर-साल आधार पर वृद्धि दर क्रमशः 95.94 प्रतिशत और 18.18 प्रतिशत रही। बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 57.6 प्रतिशत रही।

इससे साफ है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता और मांग बढ़ रही है। सिंघानिया ने कहा कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में साल-दर-साल 2.92 फीसदी की मामूली गिरावट आई है, लेकिन बाजार हिस्सेदारी 2.4 फीसदी पर बनी हुई है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में साल-दर-साल 124.2 फीसदी की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसकी मौजूदा जुलाई में बाजार हिस्सेदारी 1.02 फीसदी है।

डिजाइन, कीमत और फीचर्स के मामले में कौन ज्यादा बेहतर, दूर करें कन्फ्यूजन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। Mahindra भारतीय बाजार में अपनी SUVs के लिए जानी जाती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में Thar, XUV700, Scorpio N और XUV 3XO जैसी पॉपलर कार हैं। महिंद्रा की दो लग्जरी एसयूवी XUV700 और Scorpio N अच्छी संख्या में बिकती हैं। आइए, जान लेते हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है?

डिजाइन

Mahindra Scorpio N में SUV के क्लासिक DNA की झलक मिलती है- बॉक्सी लाइन्स, आकर्षक स्टांस और दमदार फीचर्स जो पुराने स्टाइल की ऑफ-रोड क्षमता को दर्शाते हैं। यह एसयूवी उन लोगों के लिए है, जिन्हें मजबूत डिजाइन पसंद है।

Mahindra XUV700 ज्यादा आधुनिक और अर्बन अपील देती है। स्लीक लाइन्स, लोअर प्रोफाइल और आधुनिक स्टाइलिंग संकेत इसे एक आकर्षक क्रॉसओवर बनाते हैं। XUV700 उन खरीदारों को पसंद आएगी, जो इसे व्यावहारिकता के साथ अर्बन एसयूवी तलाश रहे हैं।

इंजन

Scorpio-N और XUV700 में इंजन के मामले में एक जैसे विकल्प हैं। ये एसयूवी 2.2-लीटर डीजल और 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध हैं। इसका माउंटेड डीजल इंजन 175 bhp की शक्ति और 370 Nm का टॉर्क देता है। मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव के साथ यह वास्तव में ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर ज्यादा सहज है।

दूसरी ओर, महिंद्रा XUV700 ऑन-रोड इस्तेमाल के लिए थोड़ी ज्यादा इच्छुक है। डीजल से चलने वाला इंजन 185 bhp का पावर देता है और टॉर्क को 420 Nm तक बढ़ा दिया गया है, जो फिर से सभी यात्री वाहनों की तरह इंजन से ट्रांसवर्स तरीके से जुड़ा हुआ है।

कीमत

Scorpio N और XUV700 पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के लिए मैनुअल या ऑटोमैटिक वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं। कीमतों की बात करें तो, XUV700 रेंज 14.59 लाख रुपये की शुरुआती कीमत से लेकर 26.70 लाख रुपये तक में उपलब्ध है। वहीं, Scorpio N को 13.85 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है, जो 20.37 लाख रुपये तक जाती है।

सिट्रोएन बेसाल्ट कूप एसयूवी भारतीय बाजार में 9 अगस्त को होगी लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

सिट्रोएन बेसाल्ट कूप एसयूवी को आधिकारिक तौर पर इस शुक्रवार 9 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है कि यह 18 किमी/लीटर से 20 किमी/लीटर के बीच की फ्यूल इकोनॉमी देगी। इसके पिछले हिस्से में लगभग 470 लीटर का कार्गो एरिया है जबकि सामने की तरफ प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स हैं। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला Tata Curvv ICE से होने वाला है।

नई दिल्ली। Citroen भारतीय बाजार में Basalt Coupe SUV लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। Citroen Basalt स्टेलेंटिस ब्रांड के तहत फ्रांसीसी ऑटो निर्माता का पांचवा मॉडल होने वाली है। इसे आधिकारिक तौर पर इस शुक्रवार, 9 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जाएगा। बेसाल्ट एक कूप एसयूवी है, जिसमें अलग बॉडी प्रोफाइल और एक्सटीरियर डिजाइन लैंग्वेज है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला Tata Curvv ICE से होने वाला है।

फीचर्स और इंटीरियर

सिट्रोन बेसाल्ट में 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 7 इंच का ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए वायरलेस सपोर्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड और ऑटो-फोल्डिंग ORVMs जैसे कुछ प्रमुख केबिन फीचर हैं। इसके पिछले हिस्से में लगभग 470 लीटर का कार्गो एरिया है, जबकि सामने की तरफ प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स हैं।

इंजन और माइलेज

सिट्रोएन बेसाल्ट दो पेट्रोल मोटर और मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के बीच विकल्प के साथ आएगी। इस एसयूवी में 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल यूनिट है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा। ये लगभग 81 बीएचपी और 115 एनएम का टॉर्क प्रदान करेगा। अधिक शक्तिशाली बेसाल्ट में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल यूनिट है, जिसे ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा।

साथ ही इसमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन स्टिक भी होगी। टर्बो बेसाल्ट ट्रांसमिशन के आधार पर लगभग 108 बीएचपी और 190Nm/205 Nm का टॉर्क प्रदान करती है। उम्मीद है कि यह 18 किमी/लीटर से 20 किमी/लीटर के बीच की फ्यूल इकोनॉमी देगी।

टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने ग्रीन मोबिलिटी पर किया समझौता

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। गठबंधन का उद्देश्य ईवी और सोलर रूफटॉप सिस्टम के बीच तालमेल बनाना है, जिससे ग्राहकों को लगभग शून्य परिचालन लागत और कम कार्बन फुटप्रिंट का लाभ मिल सके।

अपनी विशेषज्ञता को लेकर टाटा समूह की दो कंपनियाँ एक व्यापक समाधान प्रदान करेंगी जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद और सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना शामिल है। इस एकीकृत दृष्टिकोण से ईवी के स्वामित्व की कुल लागत में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, साथ ही सौर ऊर्जा निवेश के लिए भुगतान अवधि भी बढ़ेगी।

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, ₹भारत की नेट ज़ीरो की ओर यात्रा केवल EV और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने से ही हासिल की जा सकती है।₹ उन्होंने कहा कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलकर हम शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता को लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं और ईवी को ग्रिड से अलग करना चाहते हैं, साथ ही ग्राहकों के लिए परिचालन लागत को कम करना चाहते हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को सब्सिडी वाले सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। ईवी और सौर ऊर्जा की पूरक प्रकृति पर जोर देते हुए टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक प्रवीर सिन्हा ने कहा, ₹ये समाधान पर्यावरण के अनुकूल और मूल्य के प्रति जागरूक ग्राहकों के एक ही समूह को आकर्षित करते हैं। यह सहयोग रूफटॉप सिस्टम और ईवी को अधिक अपनाने को बढ़ावा देगा और विवेकपूर्ण ग्राहकों के लिए पैसे बचाते हुए उत्सर्जन को कम करने में योगदान देगा।₹

सोलर रूफटॉप सेक्टर की अग्रणी कंपनी टाटा पावर का देश भर में 700 से अधिक चैनल पार्टनर्स का मजबूत नेटवर्क है। कंपनी पहले ही 1,00,000 से अधिक ग्राहकों के लिए सोलर सिस्टम लगा चुकी है। टाटा पावर के पास देश भर में 5,600 सार्वजनिक चार्जर के साथ एक व्यापक ईवी चार्जिंग नेटवर्क है।

जयपुर में बना राजस्थान का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, एक बार में चार्ज हो सकेंगी 12 इलेक्ट्रिक वाहन

परिवहन विशेष न्यूज

राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बीच राजस्थान के अलग-अलग जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जयपुर की सड़कों पर दोपहिया और चार पहिया वाहन सबसे ज्यादा दौड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही चार्जिंग स्टेशन से जुड़ा बुनियादी ढांचा भी धीरे-धीरे विकसित किया जा रहा है।

जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब बनाया गया है, जहां एक बार में 12 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किए जा सकेंगे। ज़ोबोल्ट Xobolt कंपनी द्वारा बनाए गए इस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब में दोपहिया, चार पहिया और यहां तक कि इलेक्ट्रिक बसें भी चार्ज की जा रही हैं। कंपनी ने यहां चार फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, जहां एक बार में 9 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन चार्ज किए जा सकेंगे। इसके अलावा तीन पहिया और दो पहिया वाहनों को धीरे-धीरे चार्ज करने के लिए भी चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

जोबोल्ट कंपनी Xobolt Company के मालिक योगेश मेहरा का मानना है कि पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक गुड्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अगर रिजर्वेशन फ्रेम डेवलप हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदेंगे और इससे पर्यावरण को भी काफी फायदा होगा। जयपुर में अजमेर रोड पर बना यह इलेक्ट्रिक गुड्स हब राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा प्वाइंट है, जहां बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक गुड्स चार्ज किए जा सकते हैं। इसके अलावा शहर में अन्य जगहों पर भी ऐसे रिजर्वेशन स्टेशन बनाए गए हैं, ताकि लोगों को रिजर्वेशन से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

राजस्थान में इस समय विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार भले ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात करती हो, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से एक भी सरकारी चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है, जबकि पिछले 2 सालों में पूरे राजस्थान में 20 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। वहीं जेडीए ने कहा था कि राजधानी जयपुर में 70 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।

राजस्थान की बात करें तो राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भी रियायतें दे रही है। पिछले सरकर में रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आरटीओ रजिस्ट्रेशन के तौर पर लगने वाला शुल्क माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने पर रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है।

राजस्थान में लगाए गए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर वाहन चार्ज करने की लागत की बात करें तो फास्ट चार्जर की लागत करीब 18 से 20 रुपए प्रति यूनिट है, जबकि स्लो चार्जिंग की लागत 10 से 15 रुपए प्रति यूनिट है। राजस्थान में अन्य कंपनियां धीरे-धीरे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही हैं। अब तक राजस्थान में 20 किलोवाट से लेकर 120 किलोवाट तक के चार्जर लगाए जा चुके हैं।

ओलंपियाड की तैयारी जेईई में सफलता पाने में कैसे मदद कर सकती है

विजय गर्ग

भारत में सबसे कठिन और कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) है। हर साल कई छात्र राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में प्रवेश पाने का प्रयास करते हैं। इसे पूरा करने के लिए, छात्र अक्सर बहुत सारी तैयारी करते हैं और अपने वैचारिक ज्ञान और समस्या-समाधान क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न तरीकों की तलाश करते हैं।

जेईई उम्मीदवार अपनी सफलता की संभावनाओं में सुधार कर सकते हैं और ओलंपियाड की तैयारी को अपनी अध्ययन दिनचर्या में शामिल करके उन विषयों के प्रति गहरा सम्मान और समझ प्राप्त कर सकते हैं जिनमें वे रुचि रखते हैं। भारत में सबसे कठिन और कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) है। हर साल कई छात्र राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में प्रवेश पाने का प्रयास करते हैं। इसे पूरा करने के लिए, छात्र अक्सर बहुत सारी तैयारी करते हैं और अपने वैचारिक ज्ञान और समस्या-समाधान क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न तरीकों की तलाश करते हैं। ओलंपियाड परीक्षाओं में भाग लेना एक ऐसा ही प्रभावी मार्ग है। ओलंपियाड और उनकी प्रासंगिकता को समझना ओलंपियाड प्रतिस्पर्धी परीक्षण हैं जिनका उद्देश्य कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान या गणित जैसे किसी विशेष क्षेत्र में छात्र की योग्यता को ढूंढना और विकसित करना है। ये परीक्षण, जिनकी कठिनाई स्कूल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होती है, मजबूत समस्या-समाधान कौशल के अलावा विषय वस्तु की गहन समझ की मांग करते हैं। ओलंपियाड और जेईई की तैयारी के बीच समानताएं उन्हें इस सेटिंग में प्रासंगिक बनाती हैं। दोनों में बुनियादी विचारों की ठोस समझ, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने की क्षमता और प्रभावी समय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, जेईई और ओलंपियाड पाठ्यक्रम अक्सर ओवरलैप होते हैं, जो उनके पारस्परिक लाभ को बढ़ाता है। वैचारिक स्पष्टता बढ़ाना ओलंपियाड के लिए तैयारी करने का एक बड़ा फायदा वैचारिक स्पष्टता पर ध्यान देना है। ओलंपियाड मुद्दे अपनी जटिलता और गहनता के लिए प्रसिद्ध हैं, जो विद्यार्थियों को सामग्री का गहन अध्ययन करने के लिए मजबूर करते हैं। यह गहन अध्ययन एक ठोस आधार बनाने में सहायता करता है, जो जेईई प्रश्नों के लिए आवश्यक है जो अक्सर मूल्यांकन करते हैं कि विभिन्न संदर्भों में बुनियादी विचारों को कैसे लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड (आईएनएमओ) और अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड (आईएमओ) में ऐसे प्रश्न हैं जो गणितीय विचारों और उनके संबंधों की गहरी समझ की मांग करते हैं।

इसके समान, भौतिक अवधारणाओं की गहन समझ भारतीय राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (INPhO) और अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (IPhO) दोनों का मुख्य लक्ष्य है। इन ओलंपियाड की तैयारी से छात्रों को एक मजबूत वैचारिक आधार प्राप्त होता है, जिससे जेईई पाठ्यक्रम को अपनाना आसान हो जाता है। उन्नत समस्या-समाधान कौशल विकसित करना ओलंपियाड समस्याओं को मूल और कठिन समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है; उन्हें केवल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जेईई उम्मीदवारों के लिए, ओलंपियाड तैयारी का यह घटक काफी सहायक है। विशेष रूप से जेईई एडवांस में, चुनौतीपूर्ण, एप्लिकेशन-आधारित प्रश्नों के साथ छात्रों के विश्लेषणात्मक और तार्किक तर्क कौशल का परीक्षण किया जाता है। ओलंपियाड कार्यों के माध्यम से काम करके, छात्र इन परिष्कृत समस्या-समाधान तकनीकों को निखार सकते हैं। उदाहरण के लिए, रसायन विज्ञान ओलंपियाड में ऐसे प्रश्न होते हैं जो छात्रों की महत्वपूर्ण सोच कौशल का उपयोग करने और अपरिचित संदर्भों में अपने ज्ञान को लागू करने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। इस प्रकार के अभ्यास से जेईई समस्याओं को रचनात्मक और आत्मविश्वास से संबोधित करने की क्षमता विकसित होती है। समय प्रबंधन और परीक्षा रणनीति में सुधार प्रभावी समय प्रबंधन जेईई और ओलंपियाड सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक आवश्यक योग्यता है। ओलंपियाड परीक्षाओं में आमतौर पर समय की कमी होती है जिसके लिए छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती हैकठिन कार्य. छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी करके अपने समय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के कौशल को सीधे जेईई में स्थानांतरित कर सकते हैं। ओलंपियाड छात्रों को यह भी निर्देश देता है कि परीक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण की योजना कैसे बनाएं। उन्हें अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, कठिनाई और परिचितता के अनुसार प्रश्नों को रैंक करने और दबाव के बावजूद शांत रहने का ज्ञान मिलता है। ये जेईई के लिए बहुत उपयोगी रणनीति हैं, जहां किसी व्यक्ति का प्रदर्शन इस बात से काफी प्रभावित हो सकता है कि उन्होंने परीक्षा कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित की है। आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करना एक ओलंपियाड प्रतिभागी जो अच्छा प्रदर्शन करता है, उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ सकता है। गहन तैयारी और उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुभव के कारण व्यक्ति जेईई जैसी अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए निपुण और अधिक तैयार महसूस करता है। ओलंपियाड की उपलब्धियों को शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अक्सर स्वीकार और प्रशंसा की जाती है, जिससे एक छात्र के बायोडाटा को एक और बढ़ावा मिलता है। उन्नत अध्ययन सामग्री और संसाधनों तक पहुंच जब छात्र ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो उन्हें सामान्य स्कूल पाठ्यक्रम के बाहर उन्नत अध्ययन सामग्री और उपकरणों तक पहुंच मिलती है। ओलंपियाड की तैयारी के लिए समर्पित विशेष पुस्तकें, समस्या सेट और इंटरनेट साइटें अक्सर इन विकल्पों में से होती हैं। ये संसाधन छात्रों को जेईई में जिन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं उनकी गहरी और व्यापक समझ प्राप्त करने में मदद करते हैं। जेईई के अभ्यर्थी आई.ई. की रप्रोब्लम्स इन जनरल फिजिक्सर जैसी पुस्तकों से बहुत लाभ उठा सकते हैं। इरोडोव और दिमित्री फ़ोमिन, सर्गेई जेनकिन और इलिया इटेनबर्ग द्वारा रगणितीय वृत्तर, जो अक्सर भौतिकी और गणित ओलंपियाड के लिए सुझाए जाते हैं। वे कठिन मुद्दे और संपूर्ण समाधान प्रदान करते हैं जो समस्या-समाधान क्षमताओं में सुधार करते हैं। एक मजबूत सहकर्मी नेटवर्क का निर्माण समान शैक्षणिक आकांक्षाओं वाले समान विचारधारा वाले साथियों के साथ बातचीत ओलंपियाड की तैयारी का एक सामान्य हिस्सा है। इस नेटवर्क में बहुत उत्साहजनक और प्रेरणादायक होने की क्षमता है। सहयोगात्मक रूप से समस्याओं का समाधान करना, संसाधनों का आदान-प्रदान करना और बहस करना सभी सीखने की प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। नैतिक समर्थन प्रदान करने के अलावा, जेईई की कठोर तैयारी के चरण के दौरान एक मजबूत सहकर्मी नेटवर्क सहायक हो सकता है। इन स्पर्धाओं में अच्छी प्रतिस्पर्धा करने के तात्कालिक उद्देश्य के अलावा, ओलंपियाड के लिए प्रशिक्षण के कई फायदे हैं। जेईई को क्रैक करने के लिए अन्य चीजों के अलावा वैचारिक स्पष्टता, परिष्कृत समस्या-समाधान तकनीक, समय प्रबंधन, परीक्षा रणनीति और आत्मविश्वास निर्माण पर जोर देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, अत्याधुनिक अध्ययन संसाधनों तक पहुंच और एक मजबूत सहकर्मी नेटवर्क का होना प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की तलाश में जबरदस्त फायदे हैं। जेईई उम्मीदवार अपनी सफलता की संभावनाओं में सुधार कर सकते हैं और ओलंपियाड की तैयारी को अपनी अध्ययन दिनचर्या में शामिल करके उन विषयों के प्रति गहरा सम्मान और समझ प्राप्त कर सकते हैं जिनमें वे रुचि रखते हैं। अंत में, उन्हें अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों प्रयासों में इस कठिन प्रशिक्षण से प्राप्त क्षमताओं और जानकारी से बहुत लाभ होगा।

संपादकीय

शेख हसीना का तख्तापलट

बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सडक़ों पर विद्रोह, आक्रोश और गुस्सा स्पष्ट दिख रहे थे, हिंसा दोतरफा थी, लिहाजा 366 से अधिक लोग मारे गए, नौजवानों को कफ्र्यू की भी परवाह नहीं थी, 15-20 पुलिस कर्मी भी मारे गए, करीब 11000 गिरफ्तारियां की गईं, अनुमान है कि आरक्षण पर छिड़े आंदोलन के दौरान 10 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है, लेकिन अचानक परिदृश्य तब बदला, जब प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ कर भागना पड़ा। फिलहाल वह भारतीय वायुसेना के किसी 'सेफ हाउस' में हैं। बेशक कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों ने आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन का आगाज किया था, लेकिन छात्रों के साथ युवा-शक्ति भी जुड़ गई और शेख हसीना को 'तानाशाह' और 'गैर-लोकतांत्रिक' करार देते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग लगातार उग्र होती गई। युवाओं की भीड़ में आतंकवादी, उग्रवादी, गद्दार और देशद्रोही भी थे अथवा वे सिर्फ आंदोलनकारी ही थे, शेख हसीना ने इस पर टिप्पणी भी की, तो वे ज्यादा उग्र हो गए। जिस शख्सियत ने प्रधानमंत्री के तौर पर 15 साल तक देश पर शासन किया था, उसे 15 मिनट में ही इस्तीफा देने और देश छोड़ कर चले जाने का फैसला करना पड़ा। सेना प्रमुख ने उन्हें 45 मिनट में ही देश छोड़ कर चले जाने का आग्रह किया और उनके सारे सामान की तलाशी ली गई। अचानक ये हालात किस लोकतंत्र की परिभाषा हैं? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता एवं 'मुक्ति संग्राम' लडक़र एक नए देश की स्थापना करने वाले शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा पर हथौड़े चलाए गए और बुलडोजर से उसे खंडित किया गया, यह कौनसे लोकतांत्रिक संस्कार हैं, जो देश की विरासत और धरोहर को ही ध्वस्त कर रहे हैं? बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के साथ ही एक और देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। हमने श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी ऐसे तख्तापलट देखे हैं। वहां भी भीड़ 'राष्ट्रपति भवन' के भीतर घुस गई थी। खूब हंगामा मचाया, तोडफ़ोड़ की और लूटपाट मचाई। ढाका में शेख मुजीब के म्यूजियम को भी आग के हवाले कर दिया गया।

बेशक यह लोकतंत्र नहीं, अराजकता और जंगली राजनीति है। शिकायत प्रधानमंत्री से हो सकती है, तो लोग उनसे बात कर सकते हैं। किसी आपत्तिजनक फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने आरक्षण को घटा कर मात्र 7 फीसदी कर दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी आरक्षण को कम करके 5 फीसदी कर दिया था। लोकतंत्र में मारामारी की कोई गुंजाइश नहीं होती। बहरहाल भारत इस समय ऐसे पड़ोसी देशों से घिरा है, जो अस्थिर, दिवालिया और चीनपरस्त हैं। नेपाल में फिर सत्ता बदली है और नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पूरी तरह चीनपरस्त हैं। पाकिस्तान और मालदीव के समूचे हालात ऐसे हैं कि उन्हें चीन का कर्जदार होना ही पड़ता है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल सीमावर्ती निकटस्थ भारतीय राज्य हैं, लिहाजा वहां अलर्ट घोषित किया गया है। सर्वदलीय बैठक में भी विदेश मंत्री जयशंकर ने सभी को आश्वस्त किया है कि सीमाएं सुरक्षित हैं। करीब 8000 छात्र बांग्लादेश से वापस आ चुके हैं। करीब 13,000 भारतीय अब भी वहीं हैं, लेकिन उनके लिए हालात ऐसे नहीं हैं कि उन्हें वहां से निकालने का अभियान शुरू किया जाए।

बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष एकमत हैं। फिलहाल बांग्लादेश में कोई भी सरकार नहीं है। वहां के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमां 'अंतरिम सरकार' बनाने के प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, कट्टरपंथियों पर पाबंदियां हटा ली गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की भी नजरबंदी समाप्त कर दी गई है। ऐसे देश के भारत पर असर स्वाभाविक और गंभीर हो सकते हैं। करीब 150 करोड़ रुपए रोजाना का आयात-निर्यात प्रभावित होंगे। भारत ने वहां काफी निवेश किया हुआ है। भारत अपने निर्यात में से 12 फीसदी बांग्लादेश को ही करता है। वहां 6000 से अधिक वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। कपड़ा, जूट, चमड़ा, फार्मा, चीनी मिट्टी के बर्तन, कृषि उत्पाद आदि बांग्लादेश से आयात किए जाते हैं। बहरहाल वहां सरकार बनना अनिवार्य है और वह कट्टरपंथी दलों की नहीं होनी चाहिए।

राय

आय के लिए व्यय

प्रदेश सरकारी ढांचे की किफायत, आर्थिक संसाधनों की किल्लत, वित्तीय व्यवस्था में फिजूलखर्ची की आदत, सरकारी उदारता और चुनावी प्रपंचों में ऊलजलूल वादों या गारंटियों से जूझ रहा है। राजनीतिक या चुनावी महत्त्वाकांक्षा से इतर प्रदेश की हकीकत अब पर्दानशीं नहीं रह सकती, इसलिए फैसलों के उचित-अनुचित होने की गारंटी अब आय के लिए व्यय का इंतजाम करना होगा ताकि गुजारे लायक आर्थिक बंदोबस्त हो सके। इसी तलाश में सुक्खू सरकार ने सोए हिमाचली अधिकार जगाते हुए वाटर सैस जैसे आइडिया का आविष्कार किया। अब विद्युत शैड्यूलिंग के जरिए किफायत पैदा की जा रही है। यानी केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं से अधिकृत मुफ्त विद्युत प्राप्ति के मुहाने, स्रोत से सीधे और ट्रांसमिशन शुल्क की आफत से दूर रहेंगे। इस तरह दो सौ करोड़ की अतिरिक्त आय का हिसाब बजट में जुड़ेगा। सरकार की पैनी नजर हिमकेयर योजना पर पड़ी, तो मालूम हुआ कि फर्जी भुगतान ने इस योजना का कचूमर निकाल दिया। हिमकेयर योजना आम नागरिक के उपचार के बजाय निजी स्वास्थ्य संस्थानों का बचाव करने लगी। सुक्खू सरकार इस रिसाव को रोकने के लिए तत्पर दिखाई देती है।

होम स्टे योजना के तहत पंजीकृत तीन हजार इकाइयां यूं तो पर्यटकों से लबालब होने लगीं, लेकिन सरकार की विद्युत व जलापूर्ति को घाव देने लगीं। सरकार आइंदा होम स्टे के तहत व्यापारिक दरों से ही विद्युत और पानी की आपूर्ति करेगी। सरकार को आर्थिक व्यवहार बदलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं, लेकिन केवल निजी क्षेत्र पर ही प्रहार नहीं होना चाहिए। बेशक प्रदेश की आय के लिए घाटे के स्तर तक व्यय नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए समाज के मनोविज्ञान को सही दिशा देनी होगी। सरकार को सरकार रहने दो, लेकिन प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सहभागी यानी पार्टनर चाहिए। सरकार बनाने या बचाने के हर पहलू में समाज को अपंग बनाएंगे, तो प्रदेश की आर्थिक अपंगता दूर नहीं होगी। जिस प्रदेश में बीपीएल परिवार के दोमंजिला मकान के बाहर वाहन खड़ा रहता हो, वहां लाचार कौन हुआ। जिस प्रदेश के नागरिक पड़ोसी राज्यों की रियल एस्टेट के मालिक हों, उन्हें हिमाचल में दीया दिखाने की नहीं, ईंधन बनाने की जरूरत है। किसने मांगी मुफ्त की बिजली, उधार का उपचार या शिक्षा की दीवार से सटी नई दीवार। मानना पड़ेगा कि सरकारी क्षेत्र इस प्रदेश की आर्थिकी को न आगे बढ़ा सका और न ही बचा सकता। एक निजी बस केवल रूट परमिट नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था व रोजगार है। एक रेहड़ी भी रोजगार के साथ जीएसटी उगाकर राज्य को देती है। व्यवसाय को प्रोत्साहन और रोजगार को आसमान का प्रबंध करना होगा। प्रदेश को आय के लिए निजी क्षेत्र में व्यय करना होगा।

व्यय करके नए निवेश जोन बनाने होंगे, ताकि निजी क्षेत्र में स्वरोजगार, रोजगार व जीएसटी पैदा हो सके। सरकार भूमि बैंक बनाने में निवेश करे और निजी क्षेत्र के अनुभव से दक्षता ग्रहण करे। उदाहरण के लिए एचआरटीसी के निदेशक मंडल में अगर अनुभवी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के सुझाव सुने जाएं, तो सरकारी बसें लाभकारी हो सकती हैं। पर्यटन उद्योग के निजी कंधों पर हाथ रखा जाए, तो घाटे की एचपीटीडीसी का बोझ कम होगा। राज्य की आय बढ़ाने का सूत्रधार निजी क्षेत्र हो सकता है, इसका अध्ययन महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरात में करना होगा। सरकार की आय मंदिरों में बढ़ सकती है, लेकिन पहले इन परिसरों को दक्षिण भारत के मंदिर मॉडल की तरह विकसित करना होगा। हमारे मंदिरों से पांच हजार करोड़ की आय चस्पां है, सिर्फ इस क्षमता को व्यवस्थित ढंग से चैनलाइज करने की आवश्यकता है।

हरित लॉजिस्टिक्स एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है विजय गर्ग

विजय गर्ग

त्रिकोणासन प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाली वापसी यात्राओं को कम करने से कार्बन पदचिह्न कम हो जाता है और हरित लॉजिस्टिक्स के आर्थिक लाभों पर भी जोर पड़ता है हरित माल परिवहन टिकाऊ लॉजिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण पहलू है और शिपिंग और परिवहन के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और प्रदूषण को कम करने में सक्षम बनाता है। इस क्षेत्र में आर्थिक दक्षता बढ़ाने का केंद्र कंटेनर आंदोलनों का अनुकूलन है जिसे त्रिकोणीय समाधान जैसी नवीन रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। माल परिवहन के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए हरित माल परिवहन टिकाऊ लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। पारंपरिक लॉजिस्टिक तरीकों के परिणामस्वरूप अक्सर महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरणीय गिरावट होती है। स्वच्छ वाहनों को अपनाकर, मार्गों को अनुकूलित करके और पर्यावरण-अनुकूल ईंधन का उपयोग करके, कंपनियां न केवल अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर सकती हैं बल्कि अपनी परिचालन दक्षता भी बढ़ा सकती हैं। ग्रीन लॉजिस्टिक्स के व्यावसायिक लाभ कई गुना हैं। जो कंपनियां टिकाऊ प्रथाओं में निवेश करती हैं वे ईंधन लागत पर पर्याप्त बचत प्राप्त कर सकती हैं और अपनी कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा में सुधार कर सकती हैं। ये प्रथाएँ पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बढ़ते आधार को भी आकर्षित करती हैं, वफादारी सुनिश्चित करती हैं और ब्रांड छवि को बढ़ाती हैं। इसलिए, हरित लॉजिस्टिक्स की ओर बदलाव एक पर्यावरणीय अनिवार्यता और एक रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय दोनों है। कंटेनर गतिविधियों को अनुकूलित करना: हरित माल परिवहन की आर्थिक दक्षता के लिए प्रभावी कंटेनर आवाजाही आवश्यक है। अकुशल कंटेनर प्रबंधन से ईंधन की खपत, उच्च परिचालन लागत और बढ़े हुए उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है। इन गतिविधियों को अनुकूलित करने में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कंटेनरों का पूरी तरह से उपयोग किया जाए और उनके परिवहन मार्ग यथासंभव सीधे हों। त्रिकोणासन समाधान: यह कंटेनर गतिविधियों को अनुकूलित करता है। इस पद्धति में कंटेनरों की आवाजाही को इस तरह से समन्वित करना शामिल है जिससे खाली वापसी यात्राएं कम हो जाएं। एक खाली कंटेनर को उसके मूल स्थान पर लौटाने के बजाय, त्रिकोणासन इसे एक नए गंतव्य की ओर ले जाने वाले कार्गो के साथ लोड करने की व्यवस्था करता है, इस प्रकार एक त्रिकोणीय मार्ग बनता है। उन्नत डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके, कंपनियां उन मार्गों की पहचान कर सकती हैं जहां त्रिकोणासन संभव है। इसमें शिपिंग पैटर्न, कार्गो उपलब्धता और संभावित गंतव्यों का विश्लेषण शामिल है। कंटेनरों के साथ कार्गो का मिलान: संभावित मार्गों की पहचान होने के बाद, अगला कदम उन कंटेनरों के साथ उपलब्ध कार्गो का मिलान करना है जो अन्यथा खाली लौट आएंगे। कार्यान्वयन और निगरानी: कंटेनरों के साथ कार्गो के मिलान के बाद, त्रिकोणीय मार्गों को लागू किया जाता है। निरंतर निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि मार्ग कुशल बने रहें और आवश्यकतानुसार समायोजन किया जा सके। कंटेनरों द्वारा खाली यात्रा की दूरी को कम करके, त्रिकोणासन ईंधन की खपत और उत्सर्जन को काफी कम कर देता है। यूरोपीय आयोग के एक अध्ययन में पाया गया कि कंटेनर गतिविधियों को अनुकूलित करने से उत्सर्जन में 30% तक की कटौती हो सकती है। लागत बचत: कम ईंधन खपत सीधे लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए लागत बचत में तब्दील हो जाती है। इसके अतिरिक्त, अधिक कुशल कंटेनर उपयोग से अतिरिक्त कंटेनर खरीद और रखरखाव की आवश्यकता कम हो जाती है। बढ़ी हुई परिचालन दक्षता: त्रिकोणासन परिचालन को सुव्यवस्थित करता है, जिससे परिसंपत्तियों और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। यह समग्रता को बढ़ाता हैआपूर्ति श्रृंखला की दक्षता. उन्नत डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इष्टतम मार्गों और कार्गो मैचों की पहचान करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण त्रिकोणीय मार्गों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, कंटेनर आंदोलनों की वास्तविक समय ट्रैकिंग और निगरानी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, ऐआई वास्तविक समय में रूटिंग को अनुकूलित कर सकता है। आईउटी उपकरण सभी परिचालनों में ऊर्जा के उपयोग की निगरानी और प्रबंधन कर सकते हैं। सरकारें टिकाऊ शिपिंग को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां और प्रोत्साहन बनाकर इन प्रयासों का समर्थन कर सकती हैं।

विकराल होती होती खाद्य चुनौती

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए की 'स्टेट आफ वर्ल्ड पापुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। फिलहाल जिस तेजी से विश्व की आबादी बढ़ रही है, उसके हिसाब से इसका दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। इतना ही नहीं, विश्व समुदाय के समक्ष पलायन भी एक समस्या के रूप में उभर रहा है, क्योंकि बढ़ती आबादी के चलते लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दूसरे देशों में पनाह लेने को मजबूर हैं। आज पूरी दुनिया के लिए बढ़ती आबादी और सिकुड़ते संसाधन गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की वृद्धि सीमित है। यही वजह है कि करीब आठ अरब की आबादी का बोझ ढोती यह पृथ्वी जनसंख्या से पैदा हुई अनेक समस्याओं के निदान की बाट जोह रही है। पूरी दुनिया की आबादी में अकेले एशिया की हिस्सेदारी 61 फीसद है। यही भारत के लिए दुनिया की महाशक्ति बनने में सबसे बड़ी बाधा है।

फिलहाल भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 18 फीसद है। भूभाग के लिहाज से हमारे पास 2.5 फीसद जमीन और 4 फीसद जल संसाधन है। ऐसे में तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश की सामाजिक- आर्थिक समस्याओं की जननी बनकर देश के सामने खतरे की घंटी हो सकती है। आज जनसंख्या वृद्धि देश की हर समस्या का मूल कारण बनती जा रही है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लचर स्वास्थ्य सेवाएं, अपराध, स्वच्छ पानी की कमी, इन सबके पीछे भी जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा कारण है। इतना ही नहीं, देश में जमीन के कुल साठ फीसद हिस्से पर खेती होने के बावजूद करीब बीस करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। वहीं दूसरी तरफ, जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी बड़ी जनसंख्या का आने वाले समय में पेट कैसे भरा जाए, यह भी एक अहम सवाल है। जलवायु परिवर्तन न केवल आजीविका, पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के सामने भी चुनौती खड़ी हो रही है। दुनिया के अधिकांश देश आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख है।

हालांकि यह प्रश्न कोई नया नहीं है, लेकिन इसे एक नए आयाम से देखने की आवश्यकता है। कृषि योग्य भूमि पर भी अतिक्रमण हो रहा है, इसका रकबा घट रहा है, जबकि खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं। कृषि भूमि का अन्य उपयोगों के लिए तेजी से परिवर्तन हो रहा है। किसान कृषि से दूर हो रहे हैं, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, कृषि भूमि का ह्रास भारत के सामाजिक-आर्थिक ताने- बाने को भी प्रभावित कर रहा है। हालांकि, इस दौरान सरकार द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने से जुड़ी कुछ सफल कहानियां भी हैं। बावजूद इसके, यह भी एक तथ्य है कि हमारे देश में खेती योग्य भूमि साल-दर-साल घट रही है।

'वेस्टलैंड एटलस 2019' के मुताबिक, पंजाब जैसे कृषिप्रधान राज्य में 14,000 हेक्टेयर और पश्चिम बंगाल में 62,000 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि घट गई है। वहीं, सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा सबसे अधिक खतरनाक लग सकता है, जहां हर साल विकास कार्यों के चलते 48,000 हेक्टेयर कृषि भूमि घटती जा रही है। अब गौर करने वाली बात है कि 1992 में, ग्रामीण परिवारों के पास 11.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि थी, जो 2013 तक घटकर केवल 9.2 करोड़ हेक्टेयर रह गई है। यानी महज दो दशक के अंतराल में 2.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि ग्रामीण परिवारों के हाथ से निकल गई। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कहा जा रहा है कि अगले वर्ष तक भारत में खेती का रकबा आठ करोड़ हेक्टेयर ही रह जाएगा।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में कई योजनाएं बनीं, लेकिन वे सफल नहीं हो सकीं। इसके लिए राष्ट्रीय नीति बननी बहुत जरूरी है। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या देश के विकास को प्रभावित कर रही है। बड़ी जनसंख्या तक योजनाओं का समान रूप से लाभ वितरण संभव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से दशकों बाद भी उबर नहीं सके हैं। हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी की चपेट में है। जाहिर है कि अगर आबादी बढ़ती है, तो गरीबों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। विश्व भूख सूचकांक की 2022 की रपट के मुताबिक, भारत में 16.3 फीसद आबादी कुपोषित है। पांच साल से कम उम्र के 35.5 फीसद बच्चे अविकसित हैं। भारत में 3.3 फीसद बच्चों की पांच साल की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की ताजा रपट 'द स्टेट आफ फूड सिक्युरिटी ऐंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड' के अनुसार दुनिया भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी से जूझ रहे थे। यानी दुनिया का हर दसवां शख्स भूखा है। इतना ही नहीं, रपट के अनुसार अभी भी दुनिया में 31 करोड़ लोग स्वस्थ आहार की पहुंच से बाहर हैं। साफ है, दुनिया भर में तमाम कार्यक्रमों और संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों के बावजूद खाद्य असामनता और कुपोषण को अभी तक खत्म नहीं किया जा सका है। खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक, इसका एक बड़ा कारण देशों के बीच संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मंदी है।

बहरहाल, बढ़ती आबादी के कारण ही दुनिया भर में तेल, प्राकृतिक गैसों, कोयला आदि ऊर्जा संसाधनों पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया है, जो भविष्य के लिए बड़े खतरे का संकेत है। भले हम तेज विकास को लेकर गर्व करते रहें, पर सच यह है कि दुनिया भर में भुखमरी का गंभीर संकट मंडरा रहा है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि अकाल और खाद्य समस्या का मुख्य कारण सिर्फ खाद्य पदार्थों का अभाव नहीं, बल्कि लोगों की क्रयशक्ति में कमी इसके पीछे मूल कारण है। वहीं, एक आकलन के अनुसार पूरी दुनिया में 30 फीसद अनाज बर्बाद हो जाता है। किसान भी आबादी के अनुपात में अनाज उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई बढ़ने का यह एक बड़ा कारण है। खैर, समय बदल रहा है और स्थिति भी । ऐसे में दुनिया की बड़ी आबादी को भुखमरी से बाहर निकालने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है।

जनसंख्या नियंत्रण एवं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। इन दोनों समस्याओं के निदान हेतु विश्व स्तर पर अभिनव प्रयास हो रहे हैं। भारत विश्व के उन देशों में है जहां खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपज बेहद कम है। यहां अमीर वर्ग, मध्यवर्ती किसान और व्यापारी ही उपयुक्त भोजन प्राप्त कर पाते हैं। शेष ग्रामीण, मजदूरों, लघु कृषकों, आदिवासियों, मध्यवर्गीय लोगों के समक्ष अन्न की समस्या सुरसा की तरह मुंह फैलाती जा रही है।

FY25 की पहली तिमाही में NSE का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 51 प्रतिशत बढ़ा, सरकारी कोष में दिए 14,003 करोड़ रुपये

परिवहन विशेष न्यूज

NSE ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में समेकित आधार पर 2567 करोड़ रुपये की नेट प्रॉफिट की है सालाना स्तर पर 39 प्रतिशत अधिक है। NSE ने Q1 FY25 के लिए स्टैंडअलोन आधार पर तिमाही के दौरान 1762 करोड़ रुपये का कुल खर्च किया। एनएसई ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में सरकारी खजाने में 14003 करोड़ रुपए का योगदान दिया।

नई दिल्ली। भारत के प्रमुख एक्सचेंज NSE ने FY25 की पहली तिमाही में 4,510 करोड़ रुपये का समेकित परिचालन राजस्व दर्ज किया, जो सालाना स्तर पर 51 प्रतिशत अधिक है। ट्रेडिंग रेवेन्यू के अलावा, परिचालन से राजस्व को अन्य रेवेन्यू लाइन्स द्वारा भी सपोर्ट मिला, जिसमें मुख्य रूप से डेटा सेंटर और कनेक्टिविटी फीस,क्लियरिंग सर्विस, लिस्टिंग सर्विस, इंडेक्स सर्विस और डेटा सर्विस शामिल हैं।

क्या कहते हैं आंकड़े?

एनएसई ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में समेकित आधार पर 2,567 करोड़ रुपये की नेट प्रॉफिट की है, सालाना स्तर पर 39 प्रतिशत अधिक है। FY 25 की पहली तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट मार्जिन 52 प्रतिशत रहा। समेकित आधार पर, प्रति शेयर आय वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 37.26 रुपये से बढ़कर 51.86 रुपये हो गई। ट्रेडिंग वॉल्यूम के मोर्चे पर, कैश मार्केट में औसत दैनिक ट्रेडेड वॉल्यूम (ADTV) 1,22,872 करोड़ रुपये (साल दर साल 110% की वृद्धि) दर्ज की गई, जबकि इक्विटी फ्यूचर्स ADTV 2,09,279 करोड़ रुपये (साल दर साल 101% की वृद्धि) पर पहुंच गया और इक्विटी ऑप्शन (प्रीमियम वैल्यू) ADTV Q1 FY25 के लिए 71,957 करोड़ रुपये (साल दर साल 33% की वृद्धि) पर रहा।

NSE ने स्टैंडअलोन आधार पर Q1 FY25 के लिए कुल परिचालन आय 4,051 करोड़ रुपये दर्ज की, जो साल दर साल आधार पर 43% की वृद्धि दर्शाती है, जो पिछले साल इसी तिमाही के लिए 2,833 करोड़ रुपये थी।

NSE ने किया इतना खर्च

NSE ने Q1 FY25 के लिए स्टैंडअलोन आधार पर तिमाही के दौरान 1,762 करोड़ रुपये का कुल खर्च किया। इनमें से लगभग 49% व्यय, जो 862 करोड़ रुपये है, सेबी विनियामक शुल्क, सेबी की सलाह के अनुसार कोर एसजीएफ में अतिरिक्त योगदान और आईपीएफटी में योगदान के लिए है। एनएसई ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में सेबी की सलाह के अनुसार कोर सेटलमेंट गारंटी फंड कॉर्पस को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 10,500 करोड़ रुपये करने के लिए 587 करोड़ रुपये के अतिरिक्त योगदान का प्रावधान किया है।

उपरोक्त योगदान के बाद कोर एसजीएफ का कॉर्पस 9,726 करोड़ रुपये हो जाएगा।

परिचालन EBITDA लेवल पर एनएसई ने स्टैंडअलोन आधार पर वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के लिए 59% का EBITDA मार्जिन पोस्ट किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 69% था। एनएसई ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के लिए 1,960 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल इसी तिमाही के लिए 1,598 करोड़ रुपये था। नेट स्टैंडअलोन लाभ मार्जिन 45% रहा।

किता टैक्स भरा?

एनएसई ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में सरकारी खजाने में 14,003 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जिसमें एसटीटी/सीटीटी में 12,054 करोड़ रुपए, आयकर में 236 करोड़ रुपए, स्टाम्प ड्यूटी में 1,018 करोड़ रुपए, जीएसटी में 362 करोड़ रुपए और सेबी शुल्क में 333 करोड़ रुपए शामिल थे। 12,054 करोड़ रुपए के एसटीटी में से 63% कैश मार्केट सेगमेंट से और 37% इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट से है।

Reliance ने बैलेंस शीट को किया मजबूत , विकास के अगले स्तर के लिए तैयार: अंबानी

मुकेश अंबानी ने अपने सालाना रिपोर्ट में कहा कि अस्थिरता और अनिश्चितता की दुनिया में भारत स्थिरता और समृद्धि के प्रकाशस्तंभ के रूप में चमक रहा है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी पिछले एक दशक में दूरसंचार खुदरा को अपने व्यवसाय में जोड़ा अब 2035 तक अपने परिचालन से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को लक्षित करते हुए एक हरित मार्ग पर आगे बढ़ रही है।

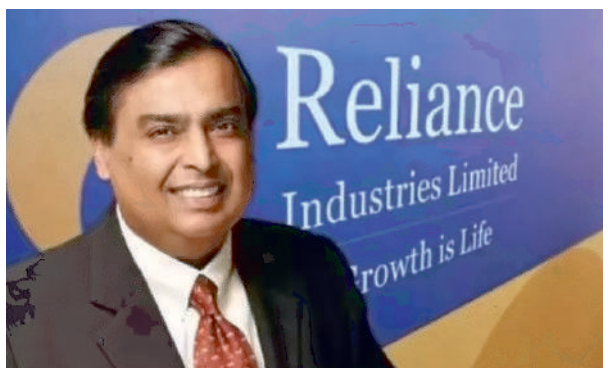

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने नेट जीरो से लेकर टू5जी टेलीकॉम नेटवर्क और रिटेल की शुरुआत तक की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए कहा कि कंपनी ने पूंजीगत व्यय के पिछले दौर के बाद अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया है और विकास के अगले स्तर के लिए तैयार है।

कंपनी की लेटेस्ट वार्षिक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अस्थिरता और अनिश्चितता की दुनिया में, भारत स्थिरता और समृद्धि के प्रकाशस्तंभ के रूप में चमक रहा है।

हरित मार्ग पर आगे बढ़ रही रिलायंस

भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी जिसने पिछले एक दशक में तेल और रसायनों के अपने मुख्य व्यवसाय में दूरसंचार, खुदरा और वित्त को जोड़ा, अब 2035 तक अपने परिचालन से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को लक्षित करते हुए एक हरित मार्ग पर आगे बढ़ रही है।

अंबानी ने कहा कि 2016 में जियो 4जी मोबाइल टेलीफोनी सेवाओं के शुभारंभ ने डेटा डार्क इंडिया को डेटा समृद्ध राष्ट्र में बदल दिया, जिससे हर भारतीय घर को किफायती, हाई-स्पीड 4जी डेटा की आपूर्ति हुई।

भारत में शुरू किया अपना टू5जी नेटवर्क

उन्होंने कहा कि इस साल, जियो ने विश्व रिकॉर्ड समय में पूरे भारत में अपना टू5जी नेटवर्क शुरू करके देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को और बढ़ाया है। खुदरा क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि भारत के सबसे बड़े खुदरा विक्रेता के रूप में, रिलायंस रिटेल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

यहां इसके उत्पादों की व्यापक रेंज लोगों तक पहुंच रही है, वहीं इसकी नई वाणिज्य पहल सिर्फ किराने के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक की होम डिलीवरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे स्वदेशी व्यापारियों और किराना दुकान मालिकों को भी समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि रिलायंस ने पूंजीगत व्यय के पिछले दौर के बाद अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया है और विकास के अगले स्तर के लिए तैयार है।

मल्टी-स्टेट कंपनियों को 1 अप्रैल, 2025 तक ISD के रूप में पंजीकरण कराना जरूरी

परिवहन विशेष न्यूज

आईटीसी के बंटवारे की व्यवस्था जीएसटी नियमों में निर्धारित है और मोटे तौर पर सामान्य आईटीसी को एक ही पैन वाली विभिन्न शाखाओं के टर्नओवर के अनुपात में विभाजित किया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अब 1 अप्रैल 2025 को बहु-राज्य शाखाओं वाली सभी कंपनियों के लिए आईएसडी के रूप में पंजीकरण करने की कट-ऑफ तिथि के रूप में अधिसूचित किया है।

नई दिल्ली। कई राज्यों में मौजूद और शाखा कार्यालयों के साथ सामान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल, 2025 तक जीएसटी अधिकारियों के साथ इनपुट सेवा वितरक (ISD) के रूप में पंजीकरण कराना होगा।

GST कानून में हुआ संशोधन

फरवरी में वित्त विधेयक 2024 के माध्यम से सरकार ने माल और सेवा कर (GST) कानून में संशोधन करते हुए कहा था कि बहु-राज्य जीएसटी पंजीकरण वाले व्यवसायों को अपनी शाखाओं के बीच प्राप्त सेवाओं के लिए किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को वितरित करने के लिए खुद को अनिवार्य रूप से आईएसडी के रूप में पंजीकृत कराना होगा।

आईटीसी के बंटवारे की व्यवस्था जीएसटी नियमों में निर्धारित है और मोटे तौर पर सामान्य आईटीसी को एक ही पैन वाली विभिन्न शाखाओं के टर्नओवर के अनुपात में विभाजित किया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अब 1 अप्रैल, 2025 को बहु-राज्य शाखाओं वाली सभी कंपनियों के लिए आईएसडी के रूप में पंजीकरण करने की कट-ऑफ तिथि के रूप में अधिसूचित किया है।

परिचालन पारदर्शिता में होगी बढ़ोतरी

मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि यह कदम परिचालन पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है और करदाताओं को उचित तरीके से राज्यों में सामान्य चालान पर कर क्रेडिट को सटीक रूप से वितरित करने में मदद करेगा।

मोहन ने कहा कि शराब, पेट्रोलियम, शिक्षा, रियल एस्टेट और स्वास्थ्य जैसे जीएसटी छूट वाले क्षेत्रों को कर क्रेडिट के प्रभावी प्रबंधन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को संरेखित करने की आवश्यकता होगी।

केपीएमजी इन इंडिया पार्टनर और हेड इनडायरेक्ट टैक्स अभिषेक जैन ने कहा कि सरकार ने आईएसडी प्रावधानों के कार्यान्वयन की उचित अवधि दी है, जिससे कंपनियों को पूरी तरह से तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। जैन ने कहा कि अब व्यवसायों को समय पर अनुपालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार होना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें गो-लाइव डेट से पहले गहन परीक्षण करने के लिए आईटी क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है।

रजिस्ट्रेशन फेल हुआ तो देना पड़ेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना, अक्टूबर से लागू होगा नियम

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब अगर निर्माता पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल होते हैं तो उन्हें 1लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इस प्रावधान के लिए 1 अक्टूबर की तारीख को अधिसूचित किया है।

नई दिल्ली। सरकार ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए जुर्माना प्रावधान लागू होने वाला है। इसके लिए सरकार ने 1 अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की है। यह जुर्माना तब लगेगा जब निर्माता पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल होंगे।

इस साल मई और जून में जीएसटी नेटवर्क दो फॉर्म जीएसटी एसआरएम- I और II अधिसूचित किए थे। निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों को पंजीकृत करने और कर अधिकारियों के साथ खरीदे गए इनपुट और संबंधित आउटपुट की रिपोर्ट करने के इन दोनों फॉर्म का इस्तेमाल होता है।

CBIC ने अधिसूचित की तारीख

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 6 अगस्त 2024 को जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीनों को पंजीकृत करने में विफलता के लिए 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने की तारीख 1 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित की।

जनवरी में CBIC ने 1 अप्रैल 2024 से पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार के लिए एक नई पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। बाद में इस तारीख को 15 मई तक बढ़ा दिया था। इसका उद्देश्य पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) अनुपालन में सुधार करना था।

फरवरी 2024 में आए वित्त विधेयक 2024 के जरिए जीएसटी कानून संशोधन किया गया। संशोधन के अनुसार पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल रहते हैं तो उन्हें को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

ये निर्माता है शामिल

यह प्रक्रिया पान-मसाला, ब्रांड नाम के साथ या उसके बिना, 'हुक्का' या 'गुडाकू' तंबाकू, पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण, चबाने वाले तंबाकू (चूने की ट्यूब के बिना) फिल्टर खैनी, जर्दा सुगंधित तम्बाकू, नसवार और ब्रांडेड या गैर-ब्रांडेड 'गुटखा' आदि निर्माताओं के लिए लागू होनी थी।

'Income Tax Refund Due' के मैसेज के बाद हो जाएं सावधान, एक भूल और लुट जाएंगे आप

आईटीआर फाइलिंग के बाज टैक्सपेयर टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कई करदाता के पास Income Tax Refund Due का मैसेज आया है। इस मैसेज में करदाता को एक नंबर पर संपर्क या लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। अगर आपके पास भी यह मैसेज आता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। यह फ्रॉड करने का नया तरीका है।

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing 2024) करने की अंतिम तारीख जा चुकी है। अब टैक्सपेयर टैक्स रिफंड (Tax Refund) का इंतजार कर रहे हैं। टैक्स रिफंड को लेकर कई टैक्सपेयर के पास Income Tax Refund Due' के मैसेज आ रहे हैं। इस मैसेज को लेकर साइबर सेल पुलिस भी लोगों को आगाह कर रही है।

दरअसल, यह एक जालसाजी भरा मैसेज है। जी हां, अगर आपके पास भी यह मैसेज आता है तो आप बिल्कुल यकीन न करें। यह मैसेज आयकर विभाग द्वारा नहीं भेजा जा रहा है।

क्या है पूरा मामला

नोएडा के साइबर सेल पुलिस ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि इस तरह के मैसेज पर बिल्कुल भी यकीन न करें। इस मैसेज पर एक नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है तो कि स्पैम नंबर होता है। अगर आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपको कई डिटेल्स जालसाज के पास पहुंच जाते हैं और आप फ्रॉड के शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे में इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए मैसेज को इग्नोर करना चाहिए।

वायरल हो रहा है लिंक

कुछ दिन पहले एक मैसेज/लिंक वायरल हो रहा है। इस मैसेज में साइबर अपराधी Income Tax Refund Due के नाम पर नंबर देता है जिस पर संपर्क करने के लिए कहा जाता है। कई बार मैसेज में लिंक भी दिया जाता है जिसे क्लिक करने की सलाह दी जाती है। इस नंबर पर संपर्क करने या लिंक पर क्लिक करके लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है।

ऐसे में इस तरह के लिंक या मैसेज से सावधान रहना चाहिए।

तुरंत करें शिकायत

अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आपको तुरंत बैंक में शिकायत करनी चाहिए ताकि अकाउंट को फ्रीज किया जाए। इसके अलावा साइबर सेल में भी शिकायत करनी चाहिए।

एमपीसी बैठक के फैसलों का कल होगा एलान, रेपो रेट को लेकर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक एमपीसी समीक्षा बैठक 6 अगस्त से शुरू हो गई है। इस बैठक के फैसलों का एलान 8 अगस्त को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किया जाएगा। इस बैठक में रेपो रेट को लेकर फैसला लिया जाता है। इस बार भी एक्सपर्ट को उम्मीद है कि रेपो रेट को स्थिर रखा जाएगा।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक 6 अगस्त से शुरू हो रही है, जिसमें रेपो रेट के भविष्य पर विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी।

वर्तमान में रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर है, जो फरवरी 2023 में अंतिम बार बदली गई थी। यह लगातार 9वीं द्विमासिक नीति समीक्षा होगी जिसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई दर और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, RBI अपनी मौजूदा नीति पर कायम रह सकता है।

मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि RBI किसी भी तरह का अचानक बदलाव नहीं करेगा। इस निर्णय का महत्व इस बात से भी है कि इससे घरेलू ऋण दरों पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे आम जनता और कारोबारी जगत पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर सभी की निगाहें इस बैठक पर लगी हुई हैं।

अश्विनी कुमार, पिरामिड इंफ्राटेक के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में हाल ही में लग्जरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की मांग में वृद्धि देखी गई है। आगामी मौद्रिक नीति से पहले, यथास्थिति में स्थिरता से इस क्षेत्र को लाभ होगा क्योंकि इससे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की मांग बढ़ेगी, जिससे डेवलपर्स को खरीदारों की जरूरतों को पूरा करने वाली अधिक प्रोजेक्ट्स बनाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, अपरिवर्तित होम लोन दरें भी संभावित घर खरीदारों को कुछ बड़ी राहत प्रदान करेंगी। हालांकि, रेपो दर में मामूली कमी से सेक्टर की वृद्धि को बल मिलेगा। इस प्रकार, हम आरबीआई के रेपो दर को स्थिर रखने के निर्णय की कल्पना करते हैं, जिससे उभरते क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट का विस्तार होगा।

कुशाग्र अंसल, डायरेक्टर अंसल हाउसिंग के अनुसार हम उम्मीद करते हैं कि यह स्वस्थ मांग प्रवृत्ति अगले कुछ वर्षों में जारी रहेगी, विशेष रूप से गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरी शहरों में, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की प्रगति का अनुभव कर रहे हैं।

रेल हादसों पर अब लगेगी लगाम! 4 साल में सभी लोकोमोटिव को किया जाएगा कवच प्रणाली से लैस

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने स्वदेशी तकनीक एवं संसाधनों से कवच का विकास किया है। इसके 4.0 वर्जन को इसी साल 17 जुलाई को पूरा किया गया है। यह जंगल पहाड़ और पानी सभी तरह की भौगोलिक स्थितियों में प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अगले चार वर्षों में ही देश के सारी ट्रेनों में कवच प्रणाली लगा दी जाएगी।

नई दिल्ली। पायलट की गलतियों से एक ही पटरी पर दो ट्रेनों के बीच होने वाले टक्कर पर जल्द नियंत्रण लग जाएगा। अगले चार वर्षों में ही देश के सारी ट्रेनों में 'कवच' प्रणाली लगा दी जाएगी। रेलवे ने अभी दस हजार किमी रेल रूट पर कवच लगाने का काम तीन कंपनियों को दिया है। बाकी रेल रूट, लोकोमोटिव एवं आठ हजार स्टेशनों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

सभी परिस्थितियों में काम करेगा कवच

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मीडिया को बताया कि रेलवे ने स्वदेशी तकनीक एवं संसाधनों से कवच का विकास किया है। इसके 4.0 वर्जन को इसी साल 17 जुलाई को पूरा किया गया है। यह जंगल, पहाड़ और पानी सभी तरह की भौगोलिक स्थितियों में प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम है।

रेल मंत्री ने बताया क्यों होते हैं हादसे ?

रेल मंत्री ने बताया कि ट्रेन हादसों के तीन बड़े कारण होते हैं। ट्रैक की खराबी, ड्राइवर की गलती एवं कभी-कभी ट्रैक पर कुछ आ जाने पर एक्सीडेंट का खतरा रहता है। कवच प्रणाली से ड्राइवर की गलतियों से होने वाले हादसों का खतरा पूरी तरह टल जाएगा। देश में अभी लगभग 20 हजार रेल इंजन हैं। प्रत्येक वर्ष करीब पांच हजार इंजनों पर कवच लगाया जाएगा। इस तरह चार वर्ष में ही सभी लोकोमोटिव में कवच प्रणाली लगा दी जाएगी।

पुराने वर्जन की कवच प्रणाली को किया जाएगा अपडेट

उन्होंने कहा कि रेल ट्रैक एवं स्टेशनों पर भी नया वर्जन का कवच लगाना है। रेलवे ने तीन कंपनियों को काम दिया है। दो अन्य कंपनियों को काम दिया जाना है। जिन रेल रूटों पर पहले से पुराने वर्जन की कवच प्रणाली लगी है, उस भी अपग्रेड किया जाएगा। नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सौ प्रतिशत स्वदेशी तकनीक एवं संसाधनों से निर्मित कवच के 4.0 वर्जन को 17 जुलाई को पूरा किया गया है।

यह जंगल, पहाड़ और पानी सभी तरह की भौगोलिक स्थितियों में प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम है। रेल मंत्री ने बताया कि कवच का नया वर्जन अभी तक सभी परीक्षणों में कवच सौ प्रतिशत खरा उतरा है। इससे ट्रेन की गति पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।

तीन हजार किमी में इसी साल पूरा होगा काम

दिल्ली-मुंबई एवं दिल्ली-हावड़ा रूट पर लगभग तीन हजार किमी में कवच लगाने का काम जारी है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से चेन्नई के लगभग 3,300 किमी रूट समेत सभी स्वचालित सिग्नलों के लिए भी निविदाएं निकाली गई हैं।

इसमें भी अक्टूबर से लगना शुरू हो जाएगा। दो सालों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद अन्य रूटों पर भी काम शुरू होगा। अगले कुछ वर्षों में ही पूरे रेल नेटवर्क पर कवच प्रणाली को तेजी से स्थापित करने में मदद मिलेगी।

भाजपा मनाएगी 'हर घर तिरंगा', 'तिरंगा यात्रा' और विभाजन स्मृति दिवसः मनमोहन सामल

मनोरंजन सासमल , स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेस्वरः पिछले कुछ वर्षों से पार्टी कार्यकर्ता हर्षुल्लाह के साथ देश की एकता और अखंडता के लिए 'हर घर तिरंगा', 'तिरंगा यात्रा' आदि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी देशवासियों के साथ मिलकर जश्न मनाते आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी.नड्डा जी के निर्देश पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने और कारावास भुगतने वालों की याद में अगले दिन 9 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रत्येक जिले में साइकिल, पदयात्रा और बाइक रैली के माध्यम से स्थानीय शहीदों को याद किया जाएगा । 11 से 14 अगस्त तक त्रिकोणीय यात्रा; 11वीं से 14वीं तक महाप्रू का चित्र एवं चारों ओर स्वच्छता अभियान; 13 से 15 अगस्त तक हर घर और मठ में ''हर घर तिरंगा'' फहराया जाएगा और महापुरुषों और दामादों के चित्रों और स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी । इसी प्रकार 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के कारण लाखों लोग मारे गये और विस्थापित हुए। देश के बंटवारे का फैसला गलत था । इस दर्दनाक दिन को 'विभाजन स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जाएगा और शाम को मौन जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि दी जाएगी । 16 अगस्त को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की जयंती मनाई जाएगी और 19 अगस्त को पवित्र ब्रह्ना बंधन मनाया जाएगा । ये सभी कार्यक्रम मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक होंगे और इसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे । प्रदेश अध्यक्ष श्री सामल ने प्रत्येक ओडिशावासी से इन सभी कार्यक्रमों में आम जनता से जुड़ने की अपील की । इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बिरची त्रिपाठी, डॉ. पूर्णचंद्र महापात्र, प्रदेश महासचिव शारदा प्रसाद शेतपथी एवं सामाचल खटेई प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

राज्यसभा की 12 सीटों के लिए तीन सितंबर को होगा चुनाव, 27 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख

चुनाव आयोग ने बुधवार (7 अगस्त 2024) को अधिसूचना जारी कर बताया कि राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव 3 सितंबर 2024 को होंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि नौ राज्यों की 12 खाली राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26-27 अगस्त है।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने नौ राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का एलान कर दिया है। बुधवार को आयोग की घोषणा के अनुसार, उपचुनाव तीन सितंबर को होंगे। 10 सीटें राज्यसभा सदस्यों के लोकसभा चुनावों में निर्वाचित होने से खाली हुई थीं, जबकि दो अन्य रिक्तियां राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से हुई हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, उपचुनाव की अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी, जबकि नामांकन 21 अगस्त तक होगा।

22 अगस्त को नामांकन-पत्रों की जांच होगी और 27 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।आयोग की ओर से कहा गया है कि जरूरी हुआ तो तीन सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम में मतगणना भी होगी। उपचुनाव छह सितंबर से पहले संपन्न हो जाना चाहिए।

गौरतलब है कि जो राज्यसभा सदस्य लोकसभा चुनावों में चुनकर आए हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (महाराष्ट्र), दीपेंद्र सिंह हुडा (हरियाणा), ज्योतिरादित्य सिंधिया (मध्य प्रदेश) और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल (राजस्थान) शामिल हैं।

लोकसभा चुनाव जीतने वालों में राजद की मीसा भारती

बिहार से लोकसभा चुनाव जीतने वालों में राजद की मीसा भारती और भाजपा के नवादा से सांसद विवेक ठाकुर तो असम से कामाख्या प्रसाद तासा और सर्बानंद सोनोवाल हैं। इनके अलावा त्रिपुरा से बिप्लब कुमार देब भी लोकसभा चुनाव जीतने वालों में शामिल हैं। इनके अलावा बीआरएस सांसद के.केशव राव ने पांच जुलाई को और बीजद सांसद ममता मोहंता ने 31 जुलाई को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था।

नौ राज्यों की 12 सीटों पर होने हैं उपचुनाव

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि उपचुनाव में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए केवल बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग मतपत्र पर वरीयताओं को चिह्नित करने के लिए किया जा सकेगा। आयोग के अनुसार, जिन नौ राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें असम की दो, बिहार की दो, महाराष्ट्र की दो और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की एक-एक सीट शामिल है।

सुप्रीमकोर्ट ने गुजरात पुलिस इंस्पेक्टर और एसीजेएम को ठहराया अवमानना का दोषी, दो सितंबर को अदालत में पेश होने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस इंस्पेक्टर को शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए एक आरोपी व्यक्ति की गलत तरीके से गिरफ्तारी और रिमांड के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। कोर्ट ने गुजरात के न्यायाधीश पर पुलिस हिरासत देने में पक्षपात करने का आरोप लगाया है।

नई दिल्ली। हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करने वाली टिप्पणी करने के लिए भले ही चेतावनी के बाद बच गए हों, लेकिन गुजरात की एक जज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना पर उसके कोपभाजन से नहीं बच पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभूतपूर्व आदेश में गुजरात के सूरत में एडिशनल चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) दीपाबेन संजयकुमार ठाकर को अपने आदेश की अवमानना का दोषी ठहराया। इतना ही नहीं कोर्ट ने सूरत के वेसु थाने में तैनात इंस्पेक्टर आरवाई रावल को भी अवमानना का दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट का अग्रिम जमानत आदेश होने के बावजूद उसकी अनदेखी कर व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में भेजने को शीर्ष अदालत ने गंभीर और अदालत की अवमानना करने वाला मानते हुए दोनों अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी माना।

कोर्ट ने दोनों को अवमानना का दोषी तो ठहराया

कोर्ट ने दोनों (जज और इंस्पेक्टर) को दो सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सजा की मात्रा पर पक्ष रखने का आदेश दिया है। यानी कोर्ट ने दोनों को अवमानना का दोषी तो ठहरा दिया है, अब बस यह तय होना है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों को अवमानना के लिए कितनी और क्या सजा देता है। ये आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने तुषार भाई रजनीकांत भाई शाह की याचिका पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को दिए।

जिस भक्ति में भय और लोभ नहीं हो वहां भक्त नहीं स्वयं भगवान मांगने आते हैं :- भागवताचार्य विष्णु महाराज

रमा विहार में श्रीमद्भ भागवत कथा श्रवण कर भक्तजन लें रहे पुण्य लाभ

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। सात दिवशीय श्रीमद्भ भागवत कथा का आज तीसरा दिन हैं जिसमें सैकड़ों भक्तजन कथा श्रवण कर अपने जीवन का उद्धार करते हुए पुण्य लाभ ले रहे हैं।

आज तीसरे दिन की कथा प्रारम्भ होने के समय भागवताचार्य पण्डित विष्णु महाराज ने कहा की जिस भक्ति में भय और लोभ नहीं हो वहां भक्त नहीं स्वयं भगवान मांगने आते हैं । तब ऐसे भक्त और उसके सम्पूर्ण परिवारजन धन्य हो जाते हैं उसका जीवन सफल हो जाता हैं उसका मोक्ष होकर हमेसा हमेसा के लिए उद्धार भी हो जाता हैं।

कथा के दौरान पण्डित विष्णु महाराज ने उपस्थित भक्तजनों के सन्मुख अपने मुखारविंद से स्वयंभू मनु के दोनों पुत्रों का वर्णन किया जिसमें बड़े प्रियव्रत हुए तो छोटे उत्तानपाद हुए । महाराज उत्तानपाद का राज्य का वर्णन किया जिसमें बताया कि महाराज उत्तानपाद के राज्य के मंदिरों के स्वर्ण कलश सूर्य की प्रथम किरणों से बात करते थे। जिसके राष्ट्र की भगवा ध्वजा संपूर्ण आसमान को पवित्र करती नजर आती थी। जिसके राज्य में मनुष्य तो क्या जानवर भी नियमों का अनुसरण करते थें। इतना ही नहीं शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। जिनके राज्य में पशुओं के वध की बात तो छोड़ दो हिंसक जानवर के वध के लिए भी राजा की अनुमति की आवश्यकता होती थी । ऐसे राजा के घर कुल ध्रुव जी का जन्म हुआ जिन्होंने भगवान की तपस्या करके बाल्यकाल में ही परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी। इनके वंश में अंग वेन आदि का भी वर्णन किया जिसमें वेन के शरीर से पृथु और अर्ची रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण का अवतार हुआ। फिर प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया जिसमें आनिद्र राजा और ऋषभदेव अवतार का वर्णन किया। फिर भरत जी का और रहूँगण राजा का संवाद करते हुए उनके जीवनी का वर्णन किया। बाद इसके नरक का वर्णन किया साथ ही अजामिल की मुक्ति का वर्णन कर तीसरे दिन की कथा को विराम दिया गया।

रामकन्या त्रिपाठी ने बताया कि कथा का आज तीसरा दिन हैं जिसमें आसपास की कॉलोनियों के श्रद्धालुओं का अटूट स्नेह मिल रहा हैं वही कथा की रसधार रमा विहार स्थित रामेश्वर महादेव मन्दिर प्रांगण में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से दोहपर 4 बजे तक धाराप्रवाह बह रही हैं। कथा की पूर्णाहुति 10 अगस्त शनिवार को होगी।

रामकन्या त्रिपाठी ने बताया कि तीसरे दिन की कथा शुरू होने से पूर्व लादुवास सरपंच मुरलीधर जौशी व प्रीति बाला जौशी के साथ ही राम ईनाणी और रितिका ईनाणी ने मिलकर स्थापित सभी देवताओं और मंडलों की विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाई।

त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान रमा विहार के राधा वल्लभ महिला मित्र मण्डली की महिलाओं में मंजु पारिक, रेखा नागला, मंजु, अनिता, पुष्पा, सजना गुर्जर, पुजा टांक, कालरा दीदी, रामू, रेखा शर्मा, ललिता, कृष्णा पार्लर, गुड्डी, रेखा भट्ट, चंचल टांक सहित महिला मण्डल की सभी महिलाएं कथा की व्यवस्थाओं को संभाल रही हैं।

राजस्थान: विधायकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे सीएम भजनलाल तो भड़क गए नेता प्रतिपक्ष, जानें वजह

राजस्थान की नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर आरोप लगाया कि वह फिल्म देखने में व्यस्त हैं जबकि राजस्थान प्रदेश अतिवृष्टि से जूझ रहा है। बता दें कि बीते दिन सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी विधायकों के साथ जयपुर स्थित सिनेमाघर में फिल्म वीर सावरकर देखने पहुंचे थे।

जयपुरः राजस्थान में भारी बारिश और उससे हुई तबाही के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फिल्म देखने जाने का मुद्दा विपक्ष के निशाने पर आ गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे 'जनता के मुंह पर तमाचा' बताया है। मंगलवार शाम को विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने विधायक साथियों के साथ फिल्म 'वीर सावरकर' देखने पहुंचे थे। इसके लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीन रखी गई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। टीकाराम जूली ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'जब आधा प्रदेश अतिवृष्टि की चपेट में है और जयपुर में ही आधा दर्जन से अधिक मृत्यु बारिश जनित दुर्घटनाओं से हो गई हो। तब राज्य के मुख्यमंत्री और सरकार का जनता के टैक्स के पैसे पर आमोद-प्रमोद में व्यस्त होना लोकतंत्र में जनता के मुंह पर तमाचे मारने जैसा है।' वीडियो में मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा स्पीकर प्रो. वासुदेव देवनानी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और दूसरे विधायक भी दिखाई दे रहे हैं। जूली ने कहा कि एक तरफ आधा राजस्थान बाढ़ की मार झेल रहा है, जयपुर में ही बारिश से आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और सरकार मौज-मस्ती में डूबी हुई है।

भारत में घुसने के फिराक में सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हुए एकत्र; BSF रख रही करीब से नजर

परिवहन विशेष न्यूज

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भारत के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने भारत में घुसने की कोशिश की लेकिन बॉर्डर सील होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया । एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि कंटीले तारों के पार इकट्ठा हुए लोग अंदर आने देने की गुहार लगा रहे थे।

जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भारत के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बुधवार को सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक एकत्र हुए और दावा किया कि उनके देश में उन पर हमला हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना झापोर्टला सीमा चौकी क्षेत्र में दक्षिण बेरुबारी गांव के पास हुई। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) बाद में उन्हें वापस ले गए।

पूरी तरह से सील है सीमाः BSF

उन्होंने कहा कि ये लोग बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले के पांच गांवों के थे जिसकी सीमा जलपाईगुड़ी से लगती है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेशी सीमा पर एकत्र हुए थे, लेकिन सीमा पूरी तरह सील होने के कारण कोई भी भारत में प्रवेश नहीं कर सका। बाद में, बीजीबी उन्हें वापस ले गया।

अंतरराष्ट्रीय सीमा जमा हुए कई बांग्लादेशी नागरिक

इस संबंध में एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि कंटीले तारों के पार इकट्ठा हुए लोग अंदर आने देने की गुहार लगा रहे थे। व्यक्ति ने कहा कि हम असहाय हैं। इस दौरान उन्होंने अपने भयावह अनुभव बताए।

बांग्लादेश में जारी है हिंसा

भीषण हिंसा के चलते शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने और भागने के लिए मजबूर होने के बाद बांग्लादेश में अनिश्चितता व्याप्त है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को संसद भंग कर दी और नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail .com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023